

गुरुवार 7 मार्च 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

एक नज़र

फेसबुक के कथित दुरुपयोग पर पूछे सवाल

संसद की एक समिति ने चुनावों के दौरान सोशल मीडिया मंच का दुरुपयोग रोकने की अमेरिकी कंपनी फेसबुक को कथित अक्षमता पर चिंता जाहिर की है। फेसबुक के उपाध्यक्ष (ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी) जोएल कपलान बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष हाजिर हुए। सूत्रों ने बताया कि फेसबुक ने यह आश्वासन दिया है कि वह चुनाव के समय अपने मंच पर विज्ञापन देने वालों की पहचान, उनका स्थान और उसका भुगतान करने वालों की पहचान एक अलग पन्ने पर उपलब्ध कराएगी।

डीएचएफएल का शेयर 11 प्रतिशत उछला

दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) का शेयर बुधवार को 11 प्रतिशत उछल गया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी ने यह पुष्टि की है कि डीएचएफएल ने रकम की हेराफेरी के लिए मुखौटा कंपनियों का सहारा नहीं लिया था। कंपनी के शेयर में इस रिपोर्ट के बाद तेजी आई। शेयर बीएसई पर 11.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 148.80 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 20 प्रतिशत तक ऊपर चला गया था। एनएसई में कंपनी का शेयर 11 प्रतिशत तेजी के साथ 148.75 रुपये पर बंद हुआ।

पृष्ठ 2

‘मंत्रालय से चुराए गए राफेल के दस्तावेज’

केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि रक्षा मंत्रालय से राफेल विमान सौदे से जुड़े दस्तावेज मौजूदा या पूर्व कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं। केंद्र ने कहा कि समाचार-पत्रों ने इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकु विमानों की खरीद में कथित गड़बड़ियों से जुड़ी खबरें प्रकाशित की हैं। महान्यायावादी के के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि ये दस्तावेज रक्षा सौदों से संबंधित हैं और शासकीय गोपनीयता अधिनियम के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन समाचार पत्रों के खिलाफ ‘आपराधिक कार्रवाई’ के बारे में विचार कर रही है, जिन्होंने ये खबरें प्रकाशित की हैं। सरकार उन याचियों पर भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने दस्तावेज का अपनी याचिका में इस्तेमाल किया है।

पृष्ठ 14

आज का सवाल		
<p>क्या नए मानक पर बैंकों को मिलेगी आरबीआई से मोहलत</p> <p>www.bshindi.com पर राय भेजें।</p> <p>आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो BSP Y और यदि न है तो BSP N लिखकर 57007 पर भेजें।</p>		
<p>पिछले सवाल का नतीजा</p> <p>क्या अमेरिका के जीएसपी दर्जा हां 60.00% वापस लेने से निर्यात होगा प्रभावित? नहीं 40.00%</p>		

सेवानिवृत्ति की उम्र तक नहीं हटेंगे अतिथि शिक्षक

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 6 मार्च

दिल्ली सरकार के निर्णय से अतिथि शिक्षकों को आज बड़ी राहत मिली। दिल्ली मंत्रिमंडल ने उस नीति मंजूरी दे दी, जिसमें अतिथि व अनुबंध वाले शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र यानी 60 वर्ष तक नहीं हटाने का प्रावधान है। सरकार को इस नीति से करीब 22 हजार अतिथि शिक्षकों को फायदा होगा। सरकार ने इस नीति को उप राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। इन शिक्षकों का अनुबंध 28 फरवरी को समाप्त हो गया था, जिसके बाद से अतिथि शिक्षक विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। मंत्रिमंडल बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस समय कुछ कक्षाओं की परीक्षाएं चल रही हैं और अगले महीने से नया सत्र शुरू होना है। ऐसे में 22 हजार अतिथि शिक्षकों को हटाने से पठन-पाठन पर असर पड़ेगा। कुल कार्यरत शिक्षकों में अतिथि

व अनुबंध पर रखे गए शिक्षकों की हिस्सा 38 फीसदी है। सिसोदिया ने कहा कि शिक्षकों के हटाए जाने से जो स्थिति आज पैदा हुई, यह आगे न हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने एक नीति को मंजूरी दी है। जिसके मुताबिक अब अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र तक काम करते रहेंगे। दिल्ली में नियमित शिक्षकों के सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है। अतिथि शिक्षकों को भी 60 साल की उम्र से पहले नहीं हटाया जाएगा। सिसोदिया ने बताया ‘चूंकि सेवा मामले उप राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए इस नीति को मंजूरी के लिए उप राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है।’

सिसोदिया ने कहा कि हरियाणा ने भी अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की उम्र तक न हटाने की नीति लागू की है। ऐसे में उप राज्यपाल को दिल्ली सरकार को इस नीति को मंजूरी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अरबबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com



►► पृष्ठ 6

मासिक कोटा बढ़ने से चीनी में गिरावट

वेंकटेश गोपालकृष्णन ►► पृष्ठ 2

अबु धाबी इन्वेस्टमेंट संग शापूजी पलोनजी का करार



डॉलर रु. 70. 30 ▼ 20 पैसे | यूरो रु. 79. 50 ▼ 40 पैसे | सोना (10ग्राम) रु. 32095 ▼ 40 रुपये | सेंसेक्स 36636. 10 ▲ 193. 60 | निफ्टी 11053. 00 ▲ 65. 50 | निफ्टी फ्यूचर्स 11086. 80 ▲ 33. 80 | ब्रैट कूड 64. 90 डॉलर ▲ 0. 10 डॉलर

नए लेखा मानक, बैंक चाहें मोहलत

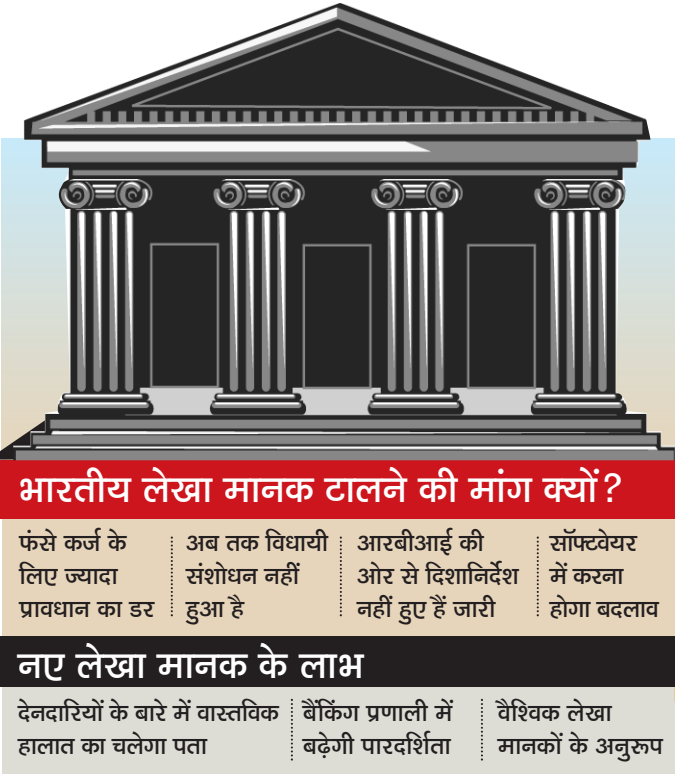
कर्ज नुकसान के लिए ज्यादा प्रावधान और लंबित विधायी संशोधनों का दिया हवाला

अभिजित लेले
मुंबई, 6 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश के मुताबिक बैंकों में भारतीय लेखा मानक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होने जा रहे हैं, लेकिन बैंक इन्हें लागू करने की तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फंसे कर्ज के लिए ज्यादा पूंजी का प्रावधान करने के अलावा लंबित विधायी संशोधनों तथा बैंकिंग नियामक द्वारा अंतिम नियमों को जारी करने में देरी का हवाला देते हुए बैंक इन्हें टालने की मांग कर रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के प्रबंध निदेशक ने कहा, ‘सरकार ने बैंकों को कठिन समय में पूंजी दी है और बैंकों पर अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने का दबाव है। भारतीय लेखा मानक लागू करने से बैंकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, खास तौर पर कर्ज नुकसान के प्रावधान के मामले में।’ इसलिए बैंक आरबीआई से कुछ मोहलत मांग रहे हैं। बैंकर ने कहा, ‘स्थिति में सुधार होने के बाद ही हम नए लेखा मानक अपनाने में सक्षम हो सकेंगे।’

आगर आरबीआई इसे टालता है तो यह दूसरा मौका होगा जब भारतीय लेखा



भारतीय लेखा मानक टालने की मांग क्यों?

फंसे कर्ज के लिए ज्यादा प्रावधान का डर	अब तक विधायी संशोधन नहीं हुआ है	आरबीआई की ओर से दिशानिर्देश नहीं हुए हैं जारी	सॉफ्टवेयर में करना होगा बदलाव
--	---------------------------------	---	-------------------------------

नए लेखा मानक के लाभ

देनदारियों के बारे में वास्तविक हालात का चलेगा पता	बैंकिंग प्रणाली में बढ़ेगी पारदर्शिता	वैश्विक लेखा मानकों के अनुरूप
--	---------------------------------------	-------------------------------

मानक लागू करने की तिथि बढ़ाई जाएगी। 2016 की आरबीआई की मूल योजना के मुताबिक बैंकों को अप्रैल 2018 से भारतीय लेखा मानक को लागू

करना था। लेकिन आरबीआई ने इसे एक साल आगे बढ़ाकर अप्रैल 2019 कर दिया क्योंकि इसके लिए जरूरी विधायी संशोधन लंबित था।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

दीवाली पर रिलायंस के ई-कॉमर्स की दस्तक

युवराज मलिक
बंगलूरु, 6 मार्च

इस साल त्योहारी मौसम में ऑनलाइन खरीदारी पर ग्राहकों को ज्यादा छूट मिल सकती है क्योंकि मुकेश मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज इस साल दीवाली पर अपने ई-कॉमर्स कारोबार की धमाकेदार दस्तक की तैयारी कर रही है। मामले से जुड़े दो सूत्रों ने कहा कि आरआईएल दीवाली पर ई-कॉमर्स कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रही है। विश्लेषकों का कहना है कि अभी तक फ्लिपकार्ट (अब वालमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी) बिग बिलियन डे और एमेज़ॉन इंडिया अपने ग्रेट इंडियन दीवाली सेल



छह शहरों में रिलायंस कर रही है अपने ई-कॉमर्स का परीक्षण

के जरिये एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती रही है। ऐसे में अंबानी के इस क्षेत्र में आने से प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो जाएगी। कंसल्टेंट्स फर्म रेडसीर के अनुसार अक्टूबर-नवंबर 2018 के दौरान ई-

कॉमर्स फर्मों ने 4.3 अरब डॉलर के सामान की बिक्री की थी।

सूत्रों ने कहा कि आरआईएल ई-कॉमर्स कारोबार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है, जिसे कंपनी के अंदर नया कॉमर्स नाम दिया गया है। इसके

तहत कंपनी अक्टूबर-नवंबर में देश भर में ई-कॉमर्स सेवा शुरू कर सकती है।

इसके लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलूरु सहित छह शहरों में परीक्षण भी किया जा रहा है। नवी मुंबई के रिलायंस कॉरपोरेट पार्क में एक समर्पित टीम

अंबानी के करीबी मनोज मोदी के नेतृत्व में इसका पूरा कामकाज देख रही है। रिलायंस की योजना अपने रिटेल नेटवर्क – रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश और रिलायंस ट्रेंड्स के साथ ही असंगठित क्षेत्र के हजारों स्टोरों को इसके साथ जोड़ने की है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

चुनाव प्रचार पर भाजपा-

कांग्रेस ने खोली तिजोरी

विवेक सुजन पटो
मुंबई, 6 मार्च

देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा अगले सप्ताह से आम चुनावों के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू कर सकते हैं। विज्ञापन उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड से इसकी पुष्टि की है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 8 या 9 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है जिसके साथ देश में आदर्श आचारसंहिता लागू हो जाएगी। इसके लागू होते ही सरकारी विज्ञापन बंद जाएंगे जो अभी मीडिया में छापे हुए हैं। इनके जरिये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार अपनी योजनाओं, नीतियों और आगे के कार्यक्रमों का प्रचार कर रही है। आचार संहिता के लागू होने के बाद भाजपा और कांग्रेस का प्रचार अभियान जोर पकड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक 2014 के चुनावों की तरह इस बार भी प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा होंगे जबकि कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी पर होगी। प्रचार के पहले दौर में भाजपा ने कम से कम 500-600 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 2014 में पार्टी ने फरवरी-मार्च से अप्रैल-मई तक अपने चुनाव प्रचार में करीब 700 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

इस बार चुनाव प्रचार की अवधि कम होगी लेकिन भाजपा इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी के प्रचार का जिम्मा ओगिल्वी समूह के पास है। वर्ष 2014 में भाजपा ने अपने प्रचार के लिए विज्ञापन एजेंसी सोहो स्ववायर (अब 82.5 कम्प्युनिकेशंस) और मैकेन वर्ल्डग्रुप की विज्ञापन कंपनी टीएजी की सेवाएं ली थी। सोहो स्ववायर ओगिल्वी समूह और का हिस्सा है। सोहो स्ववायर ने ही ‘अबकी बार मोदी सरकार’ जैसे नारे गढ़े थे जबकि मैकेन वर्ल्डग्रुप ने भाजपा का चुनावी गीत ‘सौगंध मिट्टी की’ जारी किया था। दूसरी ओर कांग्रेस आम चुनावों के लिए अभी तक प्रचार एजेंसियों को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। इसमें एफसीबी इंडिया और लिओ बनेट होड़ में हैं।

किसका कितना बजट



भाजपा : कुल खर्च (2019)*

1,100-1300
करोड़ रुपये

वर्ण **1** (केंद्र एवं राज्य द्वारा सरकारी विज्ञापनों पर खर्च)
600-700
करोड़ रुपये

वर्ण **2** (बुनाव तिथियों की घोषणा के बाद प्रचार पर खर्च)
500-600
करोड़ रुपये

2014 : 700 करोड़ रुपये

कांग्रेस : 2019 (प्रचार पर खर्च)*
200-300
करोड़ रुपये

2014 (कुल व्यय) :
500 करोड़ रुपये

*अनुमान स्रोत: विज्ञापन उद्योग

सेवानिवृत्ति की उम्र तक नहीं हटेंगे अतिथि शिक्षक

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 6 मार्च

दिल्ली सरकार के निर्णय से अतिथि शिक्षकों को आज बड़ी राहत मिली। दिल्ली मंत्रिमंडल ने उस नीति मंजूरी दे दी, जिसमें अतिथि व अनुबंध वाले शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र यानी 60 वर्ष तक नहीं हटाने का प्रावधान है। सरकार को इस नीति से करीब 22 हजार अतिथि शिक्षकों को फायदा होगा। सरकार ने इस नीति को उप राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। इन शिक्षकों का अनुबंध 28 फरवरी को समाप्त हो गया था, जिसके बाद से अतिथि शिक्षक विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। मंत्रिमंडल बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस समय कुछ कक्षाओं की परीक्षाएं चल रही हैं और अगले महीने से नया सत्र शुरू होना है। ऐसे में 22 हजार अतिथि शिक्षकों को हटाने से पठन-पाठन पर असर पड़ेगा। कुल कार्यरत शिक्षकों में अतिथि

दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस संबंध में नीति को दी मंजूरी

22 हजार
अतिथि शिक्षकों को होगा फायदा

अपनी एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान करें / पॉलिसी लोन चुकता करें

किसी भी दिन, किसी भी समय, कहीं भी!



कॉल सेंटर सर्विसेस
(022) 6827 6827
“LICHELP <POLICY NO>” एसएमएस करें एवं 9222492224 पर भेज दें
www.licindia.in देखें. Follow us : LIC India Forever

- कोई लेनदेन शुल्क नहीं *
- तेज और आसान
- चौबीस घंटे उपलब्ध
- पूर्णतः सुरक्षित

* शीत लागू

फर्जी / धोखेबाजी वाली फोन कॉल से सावधान रहें!
आईआरडीएआई इन गतिविधियों में संलग्न नहीं है जैसे बीमा पॉलिसी बेचना, बीमा या प्रीमियम के निवेश की घोषणा करना। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाली पब्लिक पोलिस शिकायत दर्ज करें।

IRDAI Regn No.: 512

L
D
I
G
I
T
A
L
C

ऑनलाइन भुगतान की सुविधाएँ उपलब्ध:

- प्रीमियम नवीकरण
- पॉलिसी लोन चुकता करें एवं लोन पर ब्याज अदा करें

- यूपीआई भीम
- डेबिट कार्ड
- क्रेडिट कार्ड
- ई-वॉलेट
- इंटरनेट बैंकिंग



हर पल आपके साथ

टिकी रह सकती है मिडकैप शेयरों में तेजी : इलारा

सुंदर सेतुगमन मुंबई, 6 मार्च

इलारा कैपिटल ने एक नोट में कहा है कि मिडकैप शेयरों में आई हालिया तेजी टिकी रह सकती है क्योंकि मूल्यांकन बेहतर हैं और इसमें सुधार की गुंजाइश है। ब्रोकरेज के मुताबिक, लार्ज और मिडकैप के बीच मूल्यांकन का अंतर हाल में ऐतिहासिक तौर पर निचले स्तर पर चला गया था, जो मिडकैप को कम आकर्षक बनाता था।

इलारा कैपिटल के शोध प्रमुख रवि मुत्थुकृष्णन ने निवेशकों को भजे नोट में कहा है, हमारा मानना है कि मिडकैप शेयरों के प्रदर्शन में सुधार के लिहाज से इन स्तरों पर मूल्यांकन बेहतर है, खास तौर से अच्छी गुणवत्ता वाले मिडकैप शेयरों में, जिन पर काफी चोट पड़ी है। बुधवार को मिडकैप व स्मॉलकैप शेयरों में तेजी जारी रही और मिडकैप 100 इंडेक्स 0.6 फीसदी चढ़ा जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई। एक दिन पहले स्मॉलकैप इंडेक्स में पांच महीने में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। छोटी कंपनियों के शेयरों में उछाल एक साल तक कमजोर प्रदर्शन के बाद देखने को मिली। नोट में कहा गया है, मिडकैप और लार्जकैप के बीच एक साल के रिटर्न (रॉलिंग) का अंतर 22 फीसदी के नकारात्मक स्तर पर पहुंच गया था जबकि इसका औसत 4.4 फीसदी रहा है।

इलारा का मानना है कि निफ्टी मिडकैप वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2021 के बीच आय में 22 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि की दर से बढ़ोतरी दर्ज करेगा। आय में बढ़ोतरी को कच्चे तेल व जिंसों की स्थिर कीमत, उपभोग के मजबूत परिदृश्य से सहारा मिलेगा। आय में मजबूत बढ़ोतरी का अनुमान ठोस फंडामेंटल का सहारा देता है। ब्रोकरेज ने हालांकि अल्पावधि में उच्च उतारचढ़ाव की संभावना से इनकार नहीं किया।

ग्लेनमार्क ने इनोवेटिव बिजनेस का सीईओ नियुक्त किया

हाल में अमेरिकी इनोवेटिव बिजनेस को अलग कर एक कंपनी के दायरे में लाने का फैसला करने वाली दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने नोवार्टिस के दिग्गज एलेसांड्रो रीवा को सीईओ नियुक्त किया है। ग्लेनमार्क के इनोवेशन कारोबार के सीईओ के तौर पर उनकी नियुक्ति 2 अप्रैल से प्रभावी होगी। फरवरी में ग्लेनमार्क ने कहा था कि निदेशक मंडल ने सैद्धांतिक तौर पर इनोवेशन कारोबार को अलग कर एक कंपनी के दायरे में लाने को मंजूरी दे दी है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में होगा। द फार्मासुस कंपनी ग्लेनमार्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक होगी और सीईओ रीवा, प्रबंधन टीम और स्वतंत्र निदेशक मंडल के नेतृत्व में परिचालन करेगी। *बीएस*

नए लेखा मानक पर बैंक चाहे मोहलत

पृष्ठ-1 का शेष

बहुराष्ट्रीय कंसल्टेंसी में अकाउंटिंग एडवाइजरी के प्रमुख ने कहा, ‘नए लेखा मानक को एक साल टालने के बाद कई बैंकों ने सॉफ्टवेयर और प्रणाली में बदलाव के काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।’ उन्होंने कहा कि इस तरह के बदलाव में कम से कम एक तिमाही का वक्त लग सकता है।वर्ष 2016 में आरबीआई ने भारतीय लेखा मानक के लिए अपने प्रारंभिक दिशानिर्देश में बैंकों से कहा था कि वह दोनों लेखा प्रारूप के बीच अंतर का विश्लेषण करें। बैंकों ने इसके बाद भारतीय लेखा मानक के आधार पर समानांतर लेखा मूल्यांकन किया।

बैंकों को भारतीय लेखा मानक के तहत प्रस्तावित तुलना के लिए पिछले साल के वित्तीय विवरण के साथ ही अप्रैल 19 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। बैंकिंग उद्योग की लॉबीइंग निकाय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने कहा कि निकट भविष्य में बैंकिंग नियामक द्वारा अंतिम नियम लेकर आने की संभावना कम ही है।’

आईबीए का कहना है कि भारतीय लेखा मानक के लिए दिशानिर्देश की अभी घोषणा नहीं की गई है। इससे संकेत मिलता है कि आरबीआई इसे टाल सकता है। पिछले साल कुछ बड़े बैंकों को पहले नए लेखा मानक अपनाने को कहा गया था लेकिन यह परवान नहीं चढ़ सका।

This is an advertisement for information purposes only and not a Prospectus announcement.

L&T FINANCE LIMITED



L&T Financial Services

Our Company was incorporated at Kolkata as Apeejay Finance Group Private Limited on November 24, 1993 as a private limited company under the Companies Act, 1956, as amended, with registration no. 2160810 and was granted a certificate of incorporation by the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata (“RoC”). Upon conversion of our Company from private limited to public limited, the name of our Company was changed to Apeejay Finance Group Limited and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was granted by the RoC on February 14, 1994. The name of our Company was further changed to Family Credit Limited and a fresh certificate of incorporation was granted by the ROC on July 12, 2007. The name of our Company was further changed to L&T Finance Limited and a fresh certificate of incorporation was granted by the ROC on March 17, 2017 pursuant to the scheme of amalgamation effective from February 13, 2017. Our Company is registered as a non-deposit accepting non-banking financial company with the Reserve Bank of India under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 bearing registration number B-05.06200. For further details, see the chapter titled “History, Main Objects and Key Agreements” on page 119 of the Shelf Prospectus. The Corporate Identification Number of our Company is U65910WB1993FLC060810.

Registered Office: Technopolis, 7th Floor, A- Wing, Plot No. - 4, Block - BP, Sector -V, Salt Lake, Kolkata 700 091, West Bengal; **Tel:** 033-66111800; **Corporate Office:** Brindavan, Plot No. 177, C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098, Maharashtra **Tel:** +91 22 6212 5000; **Fax:** +91 22 6621 7509; **Compliance Officer:** Ms. Apurva Rathod; **Tel:** +91 22 6212 5000; **Fax:** +91 22 6621 7509; **E-mail:** investorgrievances@ltps.com; **Website:** www.ltps.com

PUBLIC ISSUE BY L&T FINANCE LIMITED (“COMPANY” OR THE “ISSUER”) OF SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹ 1,000 (INDIAN RUPEES ONE THOUSAND) EACH (“SECURED NCDs”) FOR AN AMOUNT OF ₹ 50,000 LAKHS (“BASE ISSUE SIZE”) WITH AN OPTION TO RETAIN OVERSUBSCRIPTION UP TO ₹ 1,00,000 LAKH AGGREGATING UP TO 150,00,000 SECURED NCDs AMOUNTING TO ₹ 1,50,000 LAKH (“TRANCHE 1 ISSUE LIMIT”) (“TRANCHE 1 ISSUE”) WHICH IS WITHIN THE SHELF LIMIT OF ₹ 5,00,000 LAKH AND IS BEING OFFERED BY WAY OF THE TRANCHE 1 PROSPECTUS DATED FEBRUARY 22, 2019 CONTAINING INTER ALIA THE TERMS AND CONDITIONS OF TRANCHE 1 ISSUE (“TRANCHE 1 PROSPECTUS”), WHICH SHOULD BE READ TOGETHER WITH THE SHELF PROSPECTUS DATED FEBRUARY 22, 2019 (“SHELF PROSPECTUS”) FILED WITH THE REGISTRAR OF COMPANIES, KOLKATA, WEST BENGAL, (“ROC”), STOCK EXCHANGES AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (“SEBI”). THE SHELF PROSPECTUS AND TRANCHE 1 PROSPECTUS CONSTITUTES THE PROSPECTUS (“PROSPECTUS”).

THIS TRANCHE 1 ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008, AS AMENDED (THE “SEBI DEBT REGULATIONS”), THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER AS AMENDED AND TO THE EXTENT NOTIFIED.

Credit Rating: [ICRA] AAA/Stable by ICRA, CARE AAA/Stable by CARE, IND AAA/Stable by India Ratings

TRANCHE 1 ISSUE CLOSES ON THURSDAY MARCH 07, 2019*

Last date for submitting application is Thursday March 07, 2019

*Pursuant to the Tranche 1 Prospectus dated February 22, 2019, the Tranche 1 Issue opened on Wednesday, March 6, 2019 and was scheduled to close on Wednesday, March 20, 2019, with an option for early closure or extension by such period as may be decided by the authorised signatory(ies) as authorised by the Board of Directors of our Company pursuant to the resolution dated July 19, 2018 (“Authorised Personnel”). Our Company has exercised the option of early closure and the Authorized Personnel of our Company has vide letter dated March 6, 2019 decided to close the Issue on Thursday, March 07, 2019. In terms of the Tranche 1 Prospectus dated February 22, 2019 our Company is giving this public notice for such early closure.

The Application Forms will be accepted only between 10 a.m. and 3 p.m. and uploaded until 5 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as may be permitted by BSE and NSE on Thursday, March 07, 2019.

Our promoter is L&T Finance Holdings Limited. For further details see the chapter titled “Our Promoter” on page 134 of the Shelf Prospectus.

LISTING: The NCDs offered through the Tranche 1 Prospectus are proposed to be listed on the BSE Limited (“BSE”) and National Stock Exchange of India Limited (“NSE”). Our Company has received an ‘in-principle’ approval from BSE vide their letter no. DCS/BM/PI-BOND/24/18-19 dated January 24, 2019 and from NSE vide their letter no NSE/LIST/72314 dated January 24, 2019, For the purpose of the Tranche 1 Issue, NSE shall be the Designated Stock Exchange.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE RBI: The Company is having a valid certificate of registration dated May 04, 2017 issued by the Reserve Bank of India under section 45 IA of the Reserve Bank Of India Act, 1934 pursuant to change of name of Family Credit Limited. However, the RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the Company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the Company and for repayment of deposits/ discharge of liability by the Company.






DISCLAIMER CLAUSE OF THE BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE Limited nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the “Disclaimer Clause of the BSE Limited.”

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the “Disclaimer Clause of National Stock Exchange of India Limited.”

DISCLAIMER CLAUSE OF USE OF BSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the “Disclaimer Clause of BSE.”

DISCLAIMER CLAUSE OF USE OF NSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the “Disclaimer Clause of NSE.”

CREDIT RATINGS: The NCDs proposed to be issued under this Issue have been rated ‘[ICRA] AAA (stable) (pronounced as ICRA triple A with Stable outlook)’ for an amount of ₹ 5,00,000 lakhs, by ICRA Limited (“ICRA”) vide their letter dated December 21, 2018 and revalidated vide revalidation letter dated February 1, 2019 and further revalidated by a revalidation letter dated February 20, 2019, CARE AAA/ Stable (pronounced as CARE triple A with Stable Outlook) for an amount of ₹ 5,00,000 lakhs, by CARE Ratings Ltd. (“CARE”) vide their letter dated December 28, 2018 and revalidated vide revalidation letter dated January 31, 2019 and further revalidated by a revalidation letter dated February 20, 2019 and IND AAA/ Stable (pronounced as IND triple A with Stable outlook) for an amount of ₹ 5,00,000 lakhs, by India Ratings and Research Private Limited (“India Ratings”) vide their letter dated December 31, 2018 and revalidated vide revalidation letter dated January 31, 2019 and further revalidated by a revalidation letter dated February 20, 2019. The rating of NCDs by ICRA, CARE and India Ratings indicate that instruments with this rating are considered to have highest degree of safety regarding timely servicing of financial obligations and carry lowest credit risk. For the rating letter and rationale for these ratings, see Annexure A, Annexure B and Annexure C of the Tranche 1 Prospectus. This rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and investors should take their own decision. This rating is subject to revision or withdrawal at any time by the assigning rating agencies and should be evaluated independently of any other ratings.

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE			
 <p>EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED Edelweiss House; Off CST Road, Kalina, Mumbai 400 098 Maharashtra, India Tel: +91 22 4086 3535 Fax: +91 22 4086 3610 Email: ltfinance.ncds@edelweissfin.com Investor Grievance Email: customerservice.mb@edelweissfin.com Website: www.edelweissfin.com Contact Person: Mr. Lokesh Singhi SEBI Registration No.: INM0000010650</p>	 <p>A.K.CAPITAL SERVICES LIMITED 30-38 Free Press House, 3rd Floor, Free Press Journal Marg, 215, Nariman Point, Mumbai 400021 Tel: +91 22 6754 6500 Fax: +91 22 6610 0594 Email: ltfinance.ncd2019@akgroup.co.in Investor Grievance Email: investor.grievance@akgroup.co.in Website: www.akgroup.co.in Contact Person: Ms. Shilpa Pandey/Mr. Malay Shah SEBI Registration No.: INM000010411</p>	 <p>AXIS BANK LIMITED Axis House, 8th Floor, C-2, Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai, 400025 Tel: +91 22 6604 3293 Fax: +91 22 2425 2800 Email: ltps.ncd2019@axisbank.com Investor Grievance Email: investor.grievance@axisbank.com Website: www.axisbank.com Contact Person: Mr. Vikas Shinde SEBI Registration No.: INM000006104</p>	 <p>TRUST INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED 109/110, Balarama, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051 Tel: +91 22 4084 5000; Fax: +91 22 4084 5007 Email: projectvaja@trustgroup.in Investor Grievance email: customercare@trustgroup.in Website: www.trustgroup.in Contact Person: Ms Hani Jalan SEBI Registration No.: INM000011120</p>
DEBENTURE TRUSTEE**	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPLIANCE OFFICER:	COMPANY SECRETARY
 <p>CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED** GDA House, First Floor, Plot No. 85, S.No. 94&95, Bhusari Colony (Right), Kothrud, Pune – 411038 Tel: +91 (020) 2528 0081 Fax: + 91 (020) 2528 0275 Email: dt@clttrustee.com Investor Grievance Email: grievance@clttrustee.com Website: www.catalysttrustee.com Contact Person: Ms. Rakhi Kulkarni SEBI Registration No.: IND000000034</p>	<p>LINK Intime</p> <p>LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C- 101 1st Floor 247 Park LBS Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400083, Maharashtra, India Tel: +91 22 4918 6200 Fax: +91 22 4918 6195 Email: ncd.ltfm2019@linkintime.co.in Investor Grievance mail: ncd.ltfm2019@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Mr. Shanti Gopalkrishnan Registration Number: INR000004058 CIN: U67190MH1999PTC118368</p>	<p>Ms. Apurva Rathod Brindavan Building, Plot No 177, Vidyanagari Marg, CST Road, Kalina Santacruz (E), Mumbai 400 098 Tel: +91 22 6212 5000; Fax: +91 22 6621 7509 E-mail: investorgrievances@ltps.com Website: www.ltps.com</p> <p>Investors may contact the Registrar to the Issue or the Compliance Officer in case of any pre- Issue or post Issue related issues such as non-receipt of Allotment Advice, demat credit, refund orders etc.</p>	<p>Mr. Gufran Ahmed Siddiqui Brindavan Building, Plot No 177, Vidyanagari Marg, CST Road, Kalina Santacruz (E), Mumbai 400 098; Tel: +91 22 6212 5000 Fax: +91 22 6621 7509 E-mail: gufranahmed@ltps.com</p>

**Catalyst Trusteeship Limited (formerly known as GDA Trusteeship Limited) has by its letter dated December 26, 2018 given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Issue pursuant to regulation 4(4) of the Debt Regulations and for its name to be included in the Tranche 1 Prospectus and in all the subsequent periodical communications sent to the holders of the NCDs issued pursuant to this Issue. See Annexure D of the Shelf Prospectus

A copy of the Shelf Prospectus and the Tranche 1 Prospectus has been filed with the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal, in terms of section 26 and 31 of Companies Act, 2013, along with the endorsed/certified copies of all requisite documents. For further details please refer to the chapter titled “Material Contracts and Documents for Inspection” on page 102 of the Tranche 1 Prospectus.

Information as required under Section 30 of the Companies Act 2013: The Authorised Share Capital of the Company as on date of the Shelf Prospectus is ₹ 26,64,30,96, 100 divided into 2,65,43,09,610 Equity Share of ₹ 10 each and 10,00,00,000 Preference Shares of ₹ 100 each. The Paid up Equity Share Capital of the Company as on date of the Shelf Prospectus is ₹15,99,13,81,990 divided into 1,599,138,199 Equity Shares of ₹10 each. For further details in relation to share capital and capital structure of the Company, please see section “Capital Structure” on Page 57 of Shelf Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES AT THE TIME OF SIGNING OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF SHARES SUBSCRIBED FOR BY THEM: Mr. Jit Paul -10 Equity Shares; Mr. Karan Paul - 10 Equity Shares and Mr. Narinder Nath Bidani - 10 Equity Shares. Face value of Equity Shares ₹ 10 each.

Contents of Memorandum as regards objects: The main objects of our Company as contained in our Memorandum of Association are: 1.To carry on and undertake the business of financing, leasing, hire purchase and lease operations of all kinds. Purchasing, selling, hiring or letting on hire or financing deferred payments or to purchase or otherwise deal in all forms of immovable properties including lands, buildings, offices, show-rooms, shops, factories, god owns or real estates, all kinds of plant and machinery and equipment including tools, dies, moulds, appliances. Implements, instruments or apparatus, installations and fittings for domestic, industrial, commercial, trading, office or agricultural use, all kinds of vehicles whether moved, propelled or driven by motor, steam, oil, petrol, electricity or any mechanical means or power or other device and accessories of all vehicles, all types of furniture, fixtures and fittings including air-conditioners, refrigerators, televisions, video tape recorders and all other things or whatsoever nature or description capable of being uses therewith or in the manufacture, maintenance and working thereof. 2.To engage in the business of arrangement of security offering/issue of corporate bodies including making arrangements for selling or buying or subscribing to or dealing in securities, preparation of offer documents/prospectus/letters of offer, tying up with other intermediaries in securities, rendering corporate advisory service, determining financial structure of issuer, to manage portfolio of securities, to handle allotment and refund of securities to underwrite issues and to undertake all other matters connected with issue/offering of securities.3.To act as investors, share brokers, guarantors, and to subscribe for conditionally or unconditionally, to underwrite issue on commission or otherwise, take, hold, deal in and convert stocks, shares, and securities of all kinds subject to prior approval of SEBI. 4.To undertake the business of financing leasing hire purchase, lease operations of all kinds and all other businesses stated in sub-clause 1 above, electronically through internet based trading mechanisms subject to prior approval of appropriate authorities and Indian Cyber Laws as and when enacted. 5.To carry on business of an Investment Company or an Investment Trust Company, to undertake and transact trust and agency Investment, mutual fund business, financial business, financiers and for that purpose to land or invest money and negotiate loans in any form or manner, to draw, accept, endorse, discount, buy, sell and deal in bills of exchange, hundies, promissory notes and other negotiable instruments and securities and also to issue on commission, to subscribe for, underwrite, take, acquire and hold, sell and exchange, and deal in shares, stocks bonds or debentures or securities of any Government or Public authority or Company, gold and silver and bullion and to form, promote, subsidies and assist companies, syndicates and partnership, subject to compliance with SEBI regulations or any other relevant laws. 6.To act as consultants and to advise and assist on all aspects of corporate commercial and industrial management or activity including production, manufacturing, personnel, advertising and public relations, public welfare, marketing, taxation, technology Insurance, purchasing, sales, quality control, computer application, software, productivity, planning, research and development, organization, Import and export business, industrial, relations and management and to make evaluations, feasibility studies, project reports, forecasts and surveys and to give expert advice and suggest ways and means for Improving efficiency in mines, trades, plantations, business organizations, registered or cooperative societies, partnership or proprietary concerns and Industries of all kinds in India and elsewhere in the world and improvement of business management, office organization and export management to supply to and provide, maintain and operate services, facilities, conveniences, bureau and the like for the benefit of any Company to recruit and / or advice on the recruitment of staff for any Company. 7.To render consultancy services in investment matters to individuals, firms, or corporate bodies and to undertake and carry out portfolio management subject to prior approval of SEBI for portfolio management on behalf of clients in respect of their investment in shares, debentures, bonds or any other securities. 8.To act as investors, guarantors, underwriters subject to prior approval of SEBI for underwriters and financiers with the object of financing industrial enterprises to carry on and undertake all bill discounting to lend or deal with the money either with or without interest or security, including in current or deposit account with an bank or banks, other person or persons upon such terms, conditions and manner as may from time to time be determined and to receive money on deposit or loan upon such terms and conditions as our Company may approve. 9.To carry on the business of real estate and to acquire by purchase, lease, exchange development, construction, building erection, or to demolish, re-elect, alter, repair, re-model or otherwise deal in and make advances on the security of and deal in land, buildings, estates, hereditaments, roads, highways, docks, bridges, canals, dams, ports, reservoirs, or any other structural or architectural work of any kind whatsoever and for such purpose to prepare, estimates, designs, plans, specifications or models and to do such other or any act that may be requisite thereof, and to otherwise deal in offices, flats, service it (ows, chawls, factories, godowns, warehouses, shops, cinema theatres, and other conveniences of all kinds and properties of all kinds and description and to act as town-planners, surveyors, values, appraisers, decorators, furnishers, furniture makers, merchants, dealers, in cement, steel, iron, fuel, coke, wood coal, timber and other building requisites and to manufacture requisites for above and prefabricated houses, apartments and structures etc. 10.To carry on in India or elsewhere the business to establish and to act as agent, representative, surveyor, sub-insurance agent, and to otherwise deal in, market, making, market generating, consultant, advisor, collaborator or other-wise to deal in all incidental and allied activities related to insurance business as a corporate on account of insurance companies and to resell insurance products elaborated by third parties contracted insurance agent, to carry out any other type of financial activities in accordance with applicable laws, organize, manage, promote, encourage, provide, conduct, sponsor, subsidize, operate, develop and commercialize, insurance and assurance business in all its branches of life insurance and general insurance including whole life insurance, endowment insurance, double benefit and multiple benefit insurance, joint life insurance, medical insurance, group insurance, fire insurance, riot insurance, earth quake and natural calamity insurance, crop insurance, animal life insurance, loss of profit insurance, human body part, limbs and organs insurance, theft insurance, transit insurance, vehicle insurance, annuity plans, gratuity plans, fixed income plans, accidental insurance, unit linked insurance and any product to insure any credit performed by a client, any goods acquired through credit and the client itself and such other insurance, assurance, plans and schemes as may be developed from time-to-time and also the various type of mutual fund schemes, bonds, deposits, unit linked schemes, securities with different type of options as offered by companies, banks, Reserve Bank of India, Govt. of India, foreign institutions, financial institutions or other entities and also the various marketing products generated by the banks, institutions, etc. in the form of marketing, selling, distribution, agent, consultant, soliciting credit cards, personal loans, housing loans, loan against shares, loan against properties, gold loans, gold biscuits, and for the purpose to apply, approach, tender, acquire, hold, procure and obtain such rights, titles, entitlements, licenses and permissions from government, semi government, local authorities, public bodies, public institutions and government undertakings or from other authorities as may be necessary for the attainment of the objects under the Memorandum of Association.

Liability of the members of our Company: Limited

Note: Capitalized terms not defined herein shall have the same meaning as assigned to such terms in the Shelf Prospectus dated 22 February 2019 and Tranche 1 Prospectus dated 22 February 2019.

Disclaimer: L&T Finance Limited, subject to market conditions and other considerations is proposing a public issue of secured, redeemable non-convertible debentures (“Secured NCDs”) and has filed the Shelf Prospectus dated February 22, 2019 and Tranche 1 Prospectus dated February 22, 2019 are available on our website www.ltps.com, on the website of the stock exchanges www.nseindia.com, www.bseindia.com, on the website of SEBI www.sebi.gov.in and the respective web sites of the lead managers at www.edelweissfin.com, www.akgroup.co.in www.axisbank.com and www.trustgroup.in. Investors proposing to participate in the issue, should invest only on the basis of the information contained in the Shelf Prospectus dated February 22, 2019 and Tranche 1 Prospectus dated February 22, 2019. Investors should note that investment in NCDs involves a high degree of risks and for details relating to the same, please refer to Shelf Prospectus dated February 22, 2019, including the section on “Risk Factors” beginning on Page 18 of the Shelf Prospectus dated February 22, 2019.

For L&T FINANCE LIMITED

Sd/-
Dinanath Dubhashi
Non-Executive Director & Chairperson
(DIN - 03545900)

CONCEPT

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 17

अरावली को बचाएं

हरियाणा सरकार ने अरावली पर्वत शृंखला के संरक्षण से संबंधित कानून में संशोधन करके इस पर्वत शृंखला के एक अहम हिस्से को वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध करा दिया है। ऐसा करके राज्य सरकार ने न केवल अपने ही कदम से उपजी विभिन्न जटिलताओं की अनदेखी की है बल्कि उसने सर्वोच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा का भी स्पष्ट उल्लंघन

किया है। अरावली पर्वत शृंखला के पर्यावास को बचाने के लिए इन पहाड़ियों तथा आसपास के क्षेत्र में तमाम गैर-वानिकी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था। ब्रिटिश शासन ने सन 1900 में ही इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पंजाब लैंड प्रोजर्वेशन ऐक्ट (पीएलपीए) का गठन किया था। अब इन पहाड़ियों के एक बड़े हिस्से का वन होने का दर्जा छीना जा रहा

है। पर्यावरणविदों का मानना है कि यह संशोधन अरावली पर्वत शृंखला के अंत का फरमान है। अच्छी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल इसके प्रवर्तन पर रोक लगाई और इस कदम को निंदा योग्य बताया है।

692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत शृंखला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है। यह भारी प्रदूषण वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है। इसके अलावा यह थार मरुस्थल के विरुद्ध एक प्राकृतिक कवच का काम करती है।

अरावली के एक अहम हिस्से का वन का दर्जा छीने जाने की एक स्वाभाविक वजह अवैध अतिक्रमण को वैधता प्रदान करना और अरावली के वनों का अचल संपत्ति, खनन और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के रूप में

दुरुपयोग किया जाना भी है। ये गतिविधियां सन 1970 से ही जोर पकड़ रही हैं। इस पर्वत शृंखला पर लाखों की तादाद में मकान, वाणिज्यिक इमारतें और उद्योग-धंधे पहले ही शुरू हो चुके हैं। अरावली पहाड़ियों का करीब 30 फीसदी हिस्सा फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में आता है और अब से पहले यह पीएलपीए के अधीन संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित था। अकेले फरीदाबाद में कम से कम पांच वाणिज्यिक संस्थाएं, तीन अवैध कॉलोनियां और 140 से अधिक निजी फार्म हाउस तथा बैंकवेट हॉल तथा दो शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं।

भारतीय वन्यजीव संस्थान के 2017 के एक अध्ययन में कहा गया है कि अरावली पहाड़ियों का हरियाणा में आने वाला हिस्सा देश का



अजय मोहंती

कैसे दूर हो देश में रेटिंग का संकट

हाल के दिनों में रेटिंग एजेंसियों को लेकर जो भी नकारात्मक खबरें आई हैं उनके पीछे वजह यह है कि उन पर रेटिंग को बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत करने का दबाव होता है। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं तमाल बघोपाध्याय

एक राजा था जिसे सड़कों पर चलना अच्छा लगता था लेकिन वह चाहता था कि उसके पैर गंदे न हों। घोषणा की गई कि जो व्यक्ति इस समस्या का समाधान खोजेगा, उसे भारी भरकम इनाम से नवाजा जाएगा। पहला व्यक्ति हजारों झाड़ुओं के साथ आया। झाड़ू से पूरे साम्राज्य के ऊपर धूल के बादल छा गए और राजा बीमार पड़ गया। दूसरे व्यक्ति ने लाखों भेड़ों को मार कर उनका चमड़ा सड़क को ढकने के लिए इस्तेमाल किया लेकिन इससे आधा मार्ग भी नहीं ढका जा सका। आखिरकार एक मोची दरबार में आया, उसने राजा के पैरों की नाप ली और उनके लिए एक जोड़ी सैंडल बनाए। अब राजा आराम से सड़क पर घूम सकता था और उसके पैर भी गंदे नहीं होते थे।

देश में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की कमियों से जुड़ा रहे निवेशकों की समस्या हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक के बाद एक कारोबारी घरानों के डिफॉल्ट ने कर्जदारों और बॉन्डधारकों को बुरी तरह प्रभावित किया है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कंपनियों की स्थिति को लेकर निवेशकों को भ्रमित किया।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस कंपनी की रेटिंग एजेंसी इक्रा ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड

फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलएंडेएफएस) की रेटिंग को एकबारगी ही निवेश श्रेणी से खराब में, एए प्लस से डी में बदल दिया। कंपनी को सन 1997 में एएए श्रेणी मिली हुई थी और इक्रा, इंडिया रेटिंग एैंड रिसर्च और केयर रेटिंग, तीनों ने उसे एएए श्रेणी दी थी। एक अन्य एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया को हाल में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने आचार संहिता का पालन न करने के लिए दंडित किया है। इसने दो कंपनियों के डिफॉल्ट को चिह्नित करने में देरी की थी।

देश में रेटिंग की इस गड़बड़ी में सुधार के लिए इसके नियमक की समीक्षा आवश्यक है। सुझाव यह भी है कि अधिक लिए निवेशक के भुगतान वाला मॉडल अपनाया जाए। फिलहाल भुगतान कर्जदाता करते हैं। लंबे जुड़ाव के बदले इनमें चक्र्रीय बदलाव, कम से कम दो या अधिक एजेंसियों द्वारा अनिवार्य रेटिंग आदि के सुझाव भी हैं। खासतौर पर तब जबकि ऋण का आकार 100 करोड़ रुपये से अधिक हो। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इनकी तादाद बढ़ाने की बात भी कही गई है।

अमेरिका में देश क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं लेकिन वहां स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच का वर्चस्व है। हमारे यहां सात

एजेंसियां हैं लेकिन यहां भी क्रिसिल, केयर और इक्रा के पास रेटिंग कारोबार का 80 फीसदी है। बाकी का काम अन्य एजेंसियों में बंटा हुआ है।

सैद्धांतिक रूप से देखें तो दो वजहों से प्रतिस्पर्धा का स्वागत किया जाना चाहिए। एक तो शुल्क में कमी आएगी और दूसरा रेटिंग में सुधार होगा। शुल्क तो पहले ही कम है। बैंक ऋण के लिए रेटिंग का ये एजेंसियां 40,000 रुपये और ऋण उपायों की रेटिंग के लिए कुल ऋण के कुछ आधार अंक, अधिकतम 10 आधार अंक तक लेती हैं। एक आधार अंक प्रतिशत का सौवां हिस्सा होता है।

गुणवत्ता सुधार के बजाय अधिक रेटिंग एजेंसी कई बार मानक कमजोर करने का काम भी करती हैं। कुछ एजेंसियों पर यह संदेह किया गया कि वे कारोबार के लिए रेटिंग से समझौता करती हैं। ऐसे में निवेशक द्वारा भुगतान का मॉडल भी सही काम नहीं करेगा क्योंकि निवेशक और रेटिंग करने वालों में गठजोड़ हो सकता है।

अधिकांश निवेशक, खासतौर पर म्युचुअल फंड अक्सर रेटिंग को औपचारिकता मानते हैं। वे रेटिंग में गिरावट को नापसंद करते हैं क्योंकि इसका असर मूल्यांकन पर पता है और निवेश का शुद्ध

मूल्य कम होता है। अगर निवेशकों को ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पैसे खर्च करने होंगे तो वे रेटिंग एजेंसी को भुगतान क्यों करेंगे? बल्कि वे यही पैसा तथाकथित जांच परख की प्रक्रिया में व्यय करेंगे।

राजा के पैरों को धूल से बचाने वाले मोची की तरह सबसे सहज उपाय यही है कि डेट बाजार का गठन किया जाए। अभी बीमा और प्रोविडेंट फंड जैसे दीर्घकालिक निवेशक अपेक्षाकृत कमतर जगहों पर निवेश नहीं करते क्योंकि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकार एए श्रेणी से नीचे बहुत कम निवेश की इजाजत देते हैं।

बैंक भी ऐसे कर्जदार को पैसा देने को उत्सुक नहीं हैं जिसकी रेटिंग कम से कम बीबीबी न हो जो निवेश श्रेणी के लिए न्यूनतम है। ऐसे ऋण के लिए जोखिम अधिक होता है।

संक्षेप में कहें तो इसका हल उच्च प्रतिफल वाले बॉन्ड बाजार में निहित है। यहां निवेशक और बैंक अपने जोखिम का दांव लगा सकते हैं और कम रेटिंग वाले डेट प्रपत्र और निगमों के समक्ष जा सकते हैं। जब तक निवेश मानक शिथिल नहीं किए जाते तब तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उच्च रेटिंग देने के दबाव में रहेंगी। अमेरिकी बॉन्ड बाजार देश के जीडीपी का 120 फीसदी है। इसकी तुलना में भारतीय बॉन्ड बाजार जीडीपी का बमुरिक्ल 15 फीसदी है।

इन एजेंसियों द्वारा डिफॉल्ट को ढेर से पहचानने की एक वजह जीवंत आंकड़ों का न होना भी है। बैंकों को एक दिन के डिफॉल्ट के आंकड़े सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को देना होता है। रेटिंग एजेंसियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। परंतु कई एजेंसियां इसका लाभ लेती हैं और जानबूझकर डिफॉल्ट को विह्नित करने में देरी करती हैं। इसका फायदा जारीकर्ता को भी होता है और निवेशक को भी। अगर एजेंसियों को अद्यतन आंकड़ें मिलें तो वे जोखिम का बेहतर आकलन कर पाएंगी। अनदेखी करने पर उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए।

एसएंडपी और मूडीज दोनों को 2008 में मॉर्गेंज समर्थित प्रतिभूतियों की गुणवत्ता का सही आकलन न कर पाने पर दंडित किया गया था। इसके चलते ही 2008 का वित्तीय संकट आया था। 137 करोड़ डॉलर के जुर्माने के अलावा एसएंडपी ने 12.5 करोड़ डॉलर की राशि कैलिफोर्निया पब्लिक एंर्प्रायीज रिटायरमेंट सिस्टम को तथा 8 करोड़ डॉलर की राशि प्रतिभूति एवं विनियम आयोग को चुकाई। मूडीज ने न्याय विभाग को 43.75 करोड़ रुपये का जुर्माना दिया और राज्यों तथा वॉशिंगटन डीसी को 42.63 करोड़ डॉलर की राशि चुकाई गई।

हमारे देश में सेबी इन एजेंसियों पर बमुरिक्ल 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाता है। भले ही संदर्भ अलग हों लेकिन यह जुर्माना किसी भी तरह नाकाफी है।

निवेशकों को भी रेटिंग को इतनी अधिक तज्जो देनी बंद करनी होगी। उन्हें अन्य अहम संकेतकों पर भी नजर रखनी चाहिए। *(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक, लेखक एवं जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लि. के वरिष्ठ परामर्शदाता हैं)*

सबसे कमजोर वन क्षेत्र है। तेज गति से वनों का खात्मा और वहां हो रही विकास संबंधी गतिविधियां इस विशिष्ट भूक्षेत्र को नष्ट सिरे से नष्ट कर रही हैं। अरावली के राजस्थान में आने वाले हिस्से में भी हालत कोई खास बेहतर नहीं है। अरावली के इस क्षेत्र में आने वाली 128 पहाड़ियों में से 31 पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। इसके लिए भू माफिया और खनन माफिया जिम्मेदार हैं। अरावली पर्वत शृंखला का पर्यावास की दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व है। वनों को नष्ट होने से रोकने के अलावा यह राजस्थान से चलने वाली धूल भरी हवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती है और पहले ही खराब गुणवत्ता वाली हवा को कुछ हद तक बचाती है। इस क्षेत्र के भूजल रिचार्ज में भी इसकी अहम भूमिका है। इतना

ही नहीं, यह कई नदियों और जलधाराओं का स्रोत भी है। साबरमती, लूनी, चंबल और कृष्णावती इनमें प्रमुख नदियां हैं। रामदमा, धौज, बड़खल और सूरजकुंड जैसी झीलों का जलागम क्षेत्र भी यही पर्वत शृंखला है। इन पहाड़ियों में जबरदस्त जैव विविधता है। यहां अनेक प्रकार के पौधे, जीव-जंतु और पक्षी पाए जाते हैं। हरियाणा 3.59 फीसदी वन क्षेत्र के साथ देश में सबसे कम हरियाली वाला राज्य है।

ऐसे में वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कदम का बचाव करना संभव नहीं है। उम्मीद है कि राज्य सरकार पर्यावरणविदों तथा सर्वोच्च न्यायालय की बात सुनेगी और अधिनियम में किए गए संशोधन को खत्म करेगी। उसे अरावली वन क्षेत्र को बचाने और बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

जए भारत के बारे में सामरिक पूर्वानुमान लगा पाना कठिन



दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

परिचय दिया था। वर्ष 2001-02 में संसद पर आतंकी हमला होने के बाद भारत ने अपनी सेना को सीमा पर तैनात करने के बाद भी विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस बुला लिया। जल्द ही भारत ने ‘कोल्ड स्टार्ट’ सिद्धांत अपनाया जिसमें सैन्यबलों को किसी भी उकसावे की स्थिति में पाकिस्तान में घुसने का प्रावधान है। लेकिन अग्रिम सीमा पर पाकिस्तानी सेना और परमाणु हथियारों की तैनाती ने भारतीय नीति-निर्माताओं के हाथ बांध दिए।

समूची अवधि में पाक सैन्य मुख्यालय ने भारत को यह अहसास दिलाने की कोशिश की है कि भारत की तरफ से किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब देते समय वह विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा। वह ऐसे संकेत भी देता रहा कि भारत को नहीं रोक पाने पर वह परमाणु हथियारों के भी इस्तेमाल से नहीं चूकेगा। हालांकि भारत ने परमाणु हमले की सूरत में व्यापक नाभिकीय प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाया हुआ है लेकिन पाकिस्तान में कोई भी नहीं मानता है कि भारत कभी ऐसा कदम उठाएगा।

लेकिन अब ये तमाम धारणाएं अतीत की बात हो चुकी हैं। भारत ने भी अब अपना पहले से कोई अनुमान न लगाए जा सकने वाला रुख दिखाने के साथ आतंकी हमला करने वालों को सबक सिखाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति जताई है। भारत जवाबी गोलीबारी और सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर वायु शक्ति और शायद नौसैनिक शक्ति जैसे विकल्पों के बारे में भी सोच सकता है। इससे पाकिस्तान की पुरानी मान्यताएं ध्वस्त हो चुकी हैं। भारत के ठिकानों पर हमले का उसे तगड़ा जवाब मिलने का डर है।

दूसरा, भारत को अपनी मंशा



प्लेसमेंट में भी मिलने वाली नौकरियों से से अधिकांश में सालाना पैकेज बहुत कम होती है और किसी भी बड़े शहर में इस वेतन के साथ जीविकोपार्जन काफी मुश्किल होता है। कई बार छात्रों को केवल इसलिए उनके कोशल के हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। हमें इन परिस्थितियों का

शैक्षणिक संस्थाओं को केंपस प्लेसमेंट के लिए उचित मानक स्थापित करने चाहिए

स्थायी समाधान खोजना होगा। कई बार बड़ी कंपनियां नौकरी के नाम पर बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करके युवाओं के भविष्य को बांध लेती हैं। छात्रों को नौकरी के साथ मुफ्त

बचे मामलों का जल्द हो समाधान

जीएसटी परिषद द्वारा हाल में रियल एस्टेट के लिए जीएसटी दरों में की गई कटौती निश्चित तौर पर मकानों

का प्लेसमेंट करने के लिए उचित मानक स्थापित करने चाहिए

स्थायी समाधान खोजना होगा। कई बार बड़ी कंपनियां नौकरी के नाम पर बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करके युवाओं के भविष्य को बांध लेती हैं। छात्रों को नौकरी के साथ मुफ्त

की बिक्री बढ़ाएगी। लेकिन अभी भी इस उद्योग को राहत पहुंचाने वाले कुछ मामले छूट गए हैं। उम्मीद है कि परिस्थिति से अलग होती है। इस परिस्थिति से बचने के लिए ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। नियुक्ति संबंधी मौजूदा कानूनी प्रावधानों का पालन सख्ती से करना होगा। साथ ही, कैंपस प्लेसमेंट आयोजित कराने वाले संस्थानों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभ्यर्थी को चाहिए कि वह धैर्यपूर्वक नौकरी की नियुक्ति शर्तों को पढ़कर तथा संबंधित कंपनी की पृष्ठभूमि पता करके ही नौकरी प्रस्ताव पर विचार करे।

ऋषभ देव पांडेय, कोरबा

कानाफूसी

रसगुल्ले पर कड़वाहट

अगर आपको लग रहा था कि रसगुल्ले की लेकर विवाद खत्म हो गया है तो ऐसा नहीं है। एक वर्ष पहले इस मिठाई को बंगाल के रसगुल्ले के रूप में जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग मिल गया था लेकिन अब ओडिशा के लघु उद्योग नियम ने सुधार याचिका दायर करते हुए मांग कर दी है कि इस मिठाई का जीआई टैग बदलकर इसे जगन्नाथ रसगुल्ला कर दिया जाए। इस मामले की सुनवाई जीआई रजिस्ट्री को अप्रैल में करनी है और उसने ओडिशा के संस्थान से कहा है कि वह अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज जमा करे। अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहता है तो याचिका अपने आप खारिज हो जाएगी। गौरतलब है कि जून 2015 से ही ओडिशा और बंगाल रसगुल्ले पर अपने-अपने दावे को लेकर उलझे हुए हैं।

शराब और नियम

पुणे में एक राजमार्ग पर स्थित एक होटल अपने सातवें माले पर स्थित रेस्तरां में तो शराब परोसता है लेकिन भूलल के रेस्तरां में शराब नहीं दी जाती। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के ट्वीट के मुताबिक जब एक अतिथि ने इस बारे में जानकारी चाही तो कहा गया कि सीढ़ियों के माध्यम से होटल की सातवीं मंजिल और राजमार्ग के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक है। दरअसल दिसंबर 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों पर रोक लगाने के लिए राजमार्ग से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सात महीने बाद उसने स्पष्ट किया था कि यह प्रतिबंध शहर की सीमा में लागू नहीं होती। यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त होटल शहर की सीमा में आता है या नहीं और उसके मालिकों को इस छूट के बारे में जानकारी है या नहीं।



कॉलेज प्लेसमेंट का गिरता स्तर

आज के दौर में प्रतिस्पर्धा एक आम धारणा बन चुकी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ अच्छा रोजगार पाने की आशा में युवा वर्ग परिस्थिति और क्षमता के हिसाब से छोटे-बड़े शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेते हैं। विद्यालयों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते बड़े और लोकप्रिय संस्थान अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दे रहे हैं और छात्रों को भविष्य सुरक्षित करने का वादा कर रहे हैं। देश के अधिकांश संस्थान अंतिम मात्र के दौरान होने वाले प्लेसमेंट और नौकरी का प्रलोभन देते हैं लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति बहुत गंभीर है। देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर बहुत अधिक हो गई है और सरकारों के पास इसका उचित और स्थायी इलाज संभव होता दिखाई नहीं दे रहा। निजी क्षेत्र में अनुभव को वरीयता दी जा रही है और छात्रों को शुरूआती स्तर पर नौकरियां तलाशने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैंपस

इंद्रवीर गुप्ता, रायपुर

8 बीएस 200

स्टॉक पेज कैसे पढ़ें

बिजनेस स्टैंडर्ड के शेयर बाजार के पन्ने पर बीएस-200 में बनाई एक एक्सचेंज (बीएसए) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के स्मॉल और मिड कैप के आंकड़े एक ही जगह पर दिए जाते हैं। दोनों प्रमुख शेयर बाजारों में हर शेयर के मूल्य, भाव और कारोबार की हिस्टोरी 85 फीसदी है।

बीएसए 200 सूची दिन के कारोबार की बुनियादी जानकारी देता है। पिछले दिन बाजार किस भाव पर बंद हुआ था, खुलेआगे कारोबार के आंकड़े, मूल्य और अधिकतम भाव, शेयर के वॉल्यूम और गैप (प्राइस टू अनि) की जानकारी यहां दी जाती है। पिछले 52 सप्ताह के उच्चतम और निम्नतम आंकड़ों का रिफारेंस भी यहां उपलब्ध होता है। बाजार बंद के बाद एनएसई में फ्यूचर्स ट्रेडिंग की

बीएसए 200 सूची दिन के कारोबार की बुनियादी जानकारी देता है। पिछले दिन बाजार किस भाव पर बंद हुआ था, खुलेआगे कारोबार के आंकड़े, मूल्य और अधिकतम भाव, शेयर के वॉल्यूम और गैप (प्राइस टू अनि) की जानकारी यहां दी जाती है। पिछले 52 सप्ताह के उच्चतम और निम्नतम आंकड़ों का रिफारेंस भी यहां उपलब्ध होता है। बाजार बंद के बाद एनएसई में फ्यूचर्स ट्रेडिंग की

Prices	(994.10)	(992.45)	Prices	(52.15)	(52.30)
Open	999.80	997.40	Open	52.15	52.30
High	1004.35	1003.45	High	53.00	52.70
Low	986.00	984.15	Low	50.65	50.80
Close	999.15	991.95	Close	51.35	51.45
Shares	36240	3668K	Shares	546K	8060K
PE	20.50	20.35	PE	-	26.94
52 WK HL	146098	145896	52 WK HL	56.70	56.90
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(995.00)	(989.00)	PClose	(51.95)	(51.05)
Close	996.45	995.30	Close	51.35	50.65
Contract	1145	22	Contract	1117	26
Open Int.	866K	17K	Open Int.	19851K	1196K

Prices	(905.90)	(911.50)	Prices	(112.20)	(112.55)
Open	917.20	917.70	Open	112.20	112.50
High	925.00	926.95	High	113.70	113.55
Low	908.00	907.25	Low	111.00	111.20
Close	909.60	911.95	Close	112.20	112.10
Shares	30769	315K	Shares	981K	11474K
PE	22.23	22.29	PE	-	25.94
52 WK HL	146774	145474	52 WK HL	157.91	15891
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(916.10)	(919.00)	PClose	(112.90)	(113.40)
Close	916.50	920.05	Close	112.70	113.25
Contract	1104	6	Contract	5430	111
Open Int.	1709K	27K	Open Int.	57100K	780K

Prices	(18877)	(18923)	Prices	(362.70)	(362.50)
Open	19000	19000	Open	365.95	364.80
High	19050	19089	High	374.10	373.80
Low	18976	18928	Low	360.85	365.35
Close	18904	18975	Close	373.10	372.70
Shares	764	12834	Shares	1399K	699K
PE	34.41	34.36	PE	12.11	12.10
52 WK HL	240016990	24001695	52 WK HL	467239	468239
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(19037)	(1914K)	PClose	(363.75)	(362.90)
Close	19000	19076	Close	370.70	371.70
Contract	368	3	Contract	4516	71
Open Int.	138K	0K	Open Int.	5972K	162K

Prices	(240.30)	(241.15)	Prices	(123.95)	(123.80)
Open	241.00	241.15	Open	124.40	124.07
High	246.05	246.20	High	128.00	128.20
Low	238.10	238.00	Low	124.10	124.05
Close	236.45	237.80	Close	123.55	123.25
Shares	4911	9535K	Shares	9167	353K
PE	11.83	11.83	PE	45.19	45.26
52 WK HL	309212	309211	52 WK HL	13651020	13551018
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(236.80)	(239.00)	PClose	(124.75)	(124.70)
Close	236.20	236.90	Close	127.60	127.90
Contract	5123	114	Contract	1489	3
Open Int.	1679K	400K	Open Int.	1711K	8K

Prices	(713.35)	(712.85)	Prices	(222.70)	(223.10)
Open	718.00	717.30	Open	224.24	224.55
High	746.00	746.65	High	226.85	226.80
Low	716.00	714.10	Low	223.05	223.20
Close	736.45	737.80	Close	225.35	225.20
Shares	150K	24.62K	Shares	992K	192K
PE	18.96	19.00	PE	23.28	23.26
52 WK HL	309212	309211	52 WK HL	13651020	13551018
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(716.25)	(719.50)	PClose	(224.70)	(224.70)
Close	738.05	738.45	Close	226.35	226.30
Contract	5500	72	Contract	1673	14
Open Int.	2940K	50K	Open Int.	7688K	102K

Prices	(2107.50)	(2107.10)	Prices	(2796.70)	(2795.65)
Open	2107.50	2110.00	Open	2796.90	2795.00
High	2113.10	2110.30	High	2834.95	2815.00
Low	2091.95	2090.55	Low	2745.00	2742.00
Close	2103.05	2104.25	Close	2765.80	2765.85
Shares	264K	22.84K	Shares	25917	625K
PE	28.63	28.68	PE	18.17	18.17
52 WK HL	22191830	22201829	52 WK HL	38621256	38252561
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(2113.65)	(2122.15)	PClose	(2812.65)	(2820.30)
Close	2106.80	2115.85	Close	2778.95	2790.30
Contract	18389	304	Contract	472	31
Open Int.	11133K	53K	Open Int.	2130K	10K

Prices	(739.25)	(739.55)	Prices	(327.25)	(327.10)
Open	742.00	748.00	Open	323.45	327.10
High	766.70	766.50	High	325.25	325.20
Low	726.00	726.50	Low	323.75	327.10
Close	729.70	730.50	Close	254.00	255.25
Shares	880K	11223K	Shares	471K	659K
PE	7.86	7.87	PE	55.29	55.29
52 WK HL	1397516	1397575	52 WK HL	380201	380200
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(744.75)	(749.20)	PClose	(323.75)	(324.00)
Close	735.40	737.05	Close	248.30	246.85
Contract	14065	304	Contract	472	31
Open Int.	1679K	170K	Open Int.	134K	126K

Prices	(291.10)	(291.20)	Prices	(127.10)	(127.25)
Open	291.45	292.70	Open	127.45	128.90
High	297.45	298.00	High	133.65	134.00
Low	286.90	286.75	Low	128.00	127.50
Close	289.65	289.95	Close	132.70	132.25
Shares	314K	6718K	Shares	155K	3292K
PE	7.86	7.87	PE	55.29	55.29
52 WK HL	4272	4274	52 WK HL	15275	15275
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(293.25)	(294.60)	PClose	(1283.15)	(1289.20)
Close	291.60	293.60	Close	133.60	134.35
Contract	6386	94	Contract	12167	314
Open Int.	6177K	171K	Open Int.	2859K	145K

Prices	(120.20)	(120.25)	Prices	(335.95)	(335.65)
Open	120.20	121.00	Open	331.20	336.85
High	124.10	124.10	High	340.00	340.00
Low	119.25	119.30	Low	333.30	333.00
Close	128.80	119.90	Close	336.30	336.30
Shares	191K	316K	Shares	58777	1506K
PE	11.83	11.84	PE	47.77	47.85
52 WK HL	130956	130966	52 WK HL	923026	923026
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(120.75)	(121.00)	PClose	(337.30)	(336.75)
Close	120.65	121.90	Close	338.50	-
Contract	1005	8	Contract	1011	-
Open Int.	9756K	114K	Open Int.	7608K	-

Prices	(23.60)	(23.60)	Prices	(1313.40)	(1313.60)
Open	23.80	23.65	Open	1315.20	1324.40
High	24.10	24.10	High	1330.00	1324.50
Low	23.60	23.65	Low	1310.00	1324.00
Close	23.80	23.90	Close	1316.95	1316.70
Shares	432K	3924K	Shares	39904	450K
PE	10.31	10.32	PE	30.25	20.35
52 WK HL	3022	2932	52 WK HL	142583	142580
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(23.80)	(23.60)	PClose	(1322.75)	(1329.00)
Close	24.10	24.15	Close	1325.60	1331.15
Contract	215	4	Contract	1399	2
Open Int.	21033K	432K	Open Int.	1323K	10K

Prices	(116.30)	(116.30)	Prices	(182.95)	(182.95)
Open	115.55	117.00	Open	185.00	183.10
High	118.55	118.60	High	186.45	186.40
Low	114.15	114.15	Low	183.60	183.60
Close	114.65	114.65	Close	184.70	184.60
Shares	458K	6360K	Shares	113K	11439K
PE	5.27	5.27	PE	10.87	10.86
52 WK HL	11968	11968	52 WK HL	21713	216713
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(117.15)	(117.45)	PClose	(182.65)	(182.65)
Close	115.20	115.50	Close	183.20	183.40
Contract	3137	23	Contract	5755	23
Open Int.	23262K	316K	Open Int.	16652K	212K

Prices	(54.95)	(55.05)	Prices	(276.05)	(276.45)
Open	55.30	55.60	Open	276.20	277.30
High	56.60	56.60	High	282.20	282.55
Low	55.00	54.90	Low	275.55	276.40
Close	55.45	55.45	Close	276.15	276.15
Shares	1985K	26836K	Shares	123K	22161K
PE	9.07	9.07	PE	59.20	59.14
52 WK HL	9144	9144	52 WK HL	326232	326222
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(55.20)	(55.45)	PClose	(278.20)	(278.50)
Close	55.65	56.00	Close	279.75	281.20
Contract	4444	196	Contract	16507	417
Open Int.	74676K	2700K	Open Int.	77370K	1248K

Prices	(600.45)	(600.50)	Prices	(924.30)	(926.05)
Open	609.30	604.45	Open	935.00	931.80
High	623.35	623.90	High	958.00	957.50
Low	603.00	602.20	Low	930.00	927.00
Close	610.65	613.95	Close	950.90	950.10
Shares	41807	345K	Shares	955.90	199.05
PE	48.92	49.18	PE	20.49	20.48
52 WK HL	671436	671436	52 WK HL	1492826	1490280
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(603.80)	(601.50)	PClose	(931.55)	(936.70)
Close	614.50	615.45	Close	955.90	954.15
Contract	1992	26	Contract	3734	54
Open Int.	2452K	225K	Open Int.	1330K	35K

Prices	(312.25)	(312.15)	Prices	(936.85)	(936.20)
Open	312.25	312.00	Open	939.00	936.00
High	323.35	322.80	High	1015.00	1020.00
Low	311.00	311.40	Low	938.90	935.80
Close	317.50	317.60	Close	939.65	939.65
Shares	224K	2649K	Shares	58.95	59.13
PE	10.31	10.32	PE	48.98	48.98
52 WK HL	432167	435167	52 WK HL	4042634	40494320
FUTURES	Mar-28	Apr-25	FUTURES	Mar-28	Apr-25
PClose	(313.45)	(313.65)	PClose	(937.95)	(939.50)
Close	316.85	315.60	Close	939.55	939.70
Contract	3119	20	Contract	3095	52
Open Int.	3075K	318K	Open Int.	2088K	26K

यूनाइटेड बुअरिंग			यूनाइटेड स्पिरिट्स★		
(80.65)	Prices	(1379.50)/(1377.80)	Open	(567.10)	(566.75)
80.50	Open	1379.50	1382.80	Open	568.05
81.80	High	1408.25	1407.95	High	576.50
78.40	Low	1379.25	1380.00	Low	566.50
79.25	Close	1391.75	1392.40	Close	563.10
12557K	Shares	61291	1408K	Shares	73909
	PE	62.81	62.85	PE	55.04
105/61	52 WK HL	1494908	1491908	52 WK HL	73131
Apr-25	Future	Mar-28	Apr-25	Future	Mar-28
(81.45)	PClose	(1385.90)	(1402.00)	PClose	(568.85)
80.00	Close	1385.90	1406.90	Close	565.80
47	Contract	2504	10	Contract	2725
1512K	Open Int.	2606K	18K	Open Int.	10795K
					40K

[illegible]

10 शेयर बाजार

[illegible]

मुद्रा बाजार

देशी बाजार

ब्याज र

घरेलू ब्याज दरें प्रतिशत में | अंतरराष्ट्रीय ब्याज

इंड्यूमेंट

	कल	1 साह पहले	1 माह पहले	3 माह पहले	6 माह पहले	1 साल पहले
Call Rate	6.20	6.20	6.60	6.65	6.25	5.78
91 Day T-Bills	6.40	6.40	6.60	6.29	6.29	6.29
364 Day T-Bills	6.40	6.52	6.67	7.10	6.48	6.48
FBI, Milbon	6.24	6.35	6.40	6.50	6.60	6.60
1 yrs GS-CG2020-6.65% (As on Mar 05)	6.57	6.56	6.81	7.08	7.76	7.23
2 yrs GS-CG2021-8.79% (As on Mar 01)	6.88	6.93	7.03	7.38	7.83	7.23
3 yrs GS-CG2024-8.08%	6.85	7.02	7.89	7.27	7.83	7.28
4 yrs GS-CG2023-7.37%	6.97	7.12	7.32	7.37	7.83	7.23
5 yrs GS-CG2024-8.40% (As on Feb 21)	7.17	7.42	7.42	7.64	8.02	7.79
6 yrs GS-CG2025-8.20% (As on Mar 05)	7.37	7.37	7.47	7.93	8.06	7.99
8 yrs GS-CG2027-8.24%	7.56	7.64	7.69	8.09	7.99	7.99
10 yrs GS-CG2029-7.17%	7.56	7.59	7.69	8.09	7.99	7.99
10 yrs GS-CG2029-7.26% (As on Feb 25)	7.42	7.42	7.37	7.40	8.05	7.99
11 yrs GS-CG2030-8.37%	7.72	7.70	7.70	8.07	7.12	7.46
12 yrs GS-CG2031-6.68% (As on Feb 22)	7.70	7.70	7.71	7.71	8.23	8.02
13 yrs GS-CG2032-7.95% (As on Feb 20)	7.73	7.73	7.66	7.94	8.09	7.92
16 yrs GS-CG2035-7.40% (As on Mar 01)	7.63	7.63	7.63	7.83	7.83	7.83
17 yrs GS-CG2040-8.30%	7.78	7.74	7.76	7.89	7.89	7.42
23 yrs GS-CG2042-8.30%	7.74	7.74	7.65	7.65	8.11	7.94
24 yrs GS-CG2043-9.23% (As on Feb 22)	7.73	7.73	7.73	7.73	8.16	8.00
26 yrs GS-CG2044-8.13%	7.66	7.66	7.66	7.66	8.36	8.00
27 yrs GS-CG2046-7.06% (As on Feb 28)	7.75	7.73	7.66	7.81	8.32	7.67
36 yrs GS-CG2055-7.72% (As on Feb 28)	7.75	7.73	7.65	7.84	8.06	7.93
Bank rate	6.50	6.50	6.75	6.75	6.75	6.25
8.9500-45 (6 major banks)	8.9500-45	8.9500-45	8.9500-45	8.9500-45	8.9500-45	8.9500-45
6.250-50	6.250-50	6.250-50	6.250-50	6.250-50	6.250-50	6.250-50
Deposit rate	6.250-50	6.250-50	6.250-50	6.250-50	6.250-50	6.250-50

	अमेरिकी ट्रेजरी	1 साल पहले
3 months bill	2.44	1.66
2 years bond	2.54	2.25
3 years bond	2.52	2.42
5 years bond	2.52	2.66
10 years bond	2.72	2.89
30 years bond	3.08	3.16

	यूक्रे ट्रेजरी	वाईडीएम 1 साल पहले
3 months bill	0.77	
2 years bond	0.77	0.84
3 years bond	0.83	0.89

Instrument Open, High, Low, Close
[No of Contracts, Value#]

CURRENCY FUTURES ON NSE

EuroINR 1.137, 1.138, 1.135, 1.136 [10774, 122.36]	37.7K	Mar 27, 2019
EuroINR 80.858, 80.88, 80.158, 80.24 [78406, 639.03]	47.6K	Mar 27, 2019
EuroINR 81.21, 81.405, 80.673, 80.748 [11904, 9634.26]	14.8K	Apr 26, 2019
EuroINR 81.693, 81.693, 81.25, 81.25 [448, 365.19]	1.1K	May 29, 2019
EuroINR 82.138, 82.138, 81.988, 81.988 [94, 77.05]	152	Jun 26, 2019
GBPINR 94.01, 94.05, 93.03, 93.11 [152206, 142305.54]	52.5K	Mar 27, 2019
GBPINR 94.35, 94.443, 93.575, 93.643 [11956, 11241.35]	15.4K	Apr 26, 2019
GBPINR 94.839, 94.89, 94.004, 94.008 [700, 661.23]	720	May 29, 2019
GBPINR 95.28, 95.28, 94.67, 94.67 [59, 56]	668	Jun 26, 2019
GBPINR 95.95, 95.95, 94.92 [1, 9]	43	Jul 29, 2019
GBPUSD 1.319, 1.326, 1.312, 1.314 [14789, 194.75]	5.5K	Mar 27, 2019
GBPUSD 1.33, 1.315, 1.315, [23, 0.3]	17	Apr 26, 2019
USDINR 1.418, 1.188, 70.613, 70.626 [2356510, 166990.1]	16L	Mar 27, 2019
USDINR 71.455, 71.498, 70.915, 70.975 [340670, 242390.7]	4L	Apr 26, 2019
USDINR 71.67, 71.67, 71.16, 71.215 [11940, 854.05]	1L	May 29, 2019
USDINR 71.913, 71.913, 71.4, 71.458 [4946, 3539.64]	45.5K	Jun 26, 2019
USDINR 72.17, 72.17, 71.66 [2682, 164.11]	12.4K	Jun 26, 2019
USDINR 72.32, 72.32, 71.89, 71.868 [1158, 1092.57]	13.6K	Aug 28, 2019
USDINR 42.72, 42.73, 72.07, 72.07 [159, 114.91]	5.5K	Sep 26, 2019
USDINR 72.77, 72.77, 72.308, 72.31 [298, 215.93]	5.3K	Oct 29, 2019
USDINR 72.07, 72.07, 72.538, 72.538 [338, 338.33]	13.2K	Nov 27, 2019

Instrument Open, High, Low, Close
[No of Contracts, Value#]

CURRENCY FUTURES ON NSE

YenINR 63.76, 63.766, 63.21, 63.273 [28461, 18064.33]	31.5K	Mar 27, 2019
YenINR 64.33, 64.33, 63.645, 63.705 [3030, 1935.75]	7.1K	Apr 26, 2019
YenINR 64.45, 64.45, 64.64, 64.54 [34, 34.73]	3.1K	May 29, 2019
YenINR 64.49, 64.49, 64.3, 64.3 [10, 6.46]	5	Jun 26, 2019

CURRENCY FUTURES ON NSE

EuroINR 80.815, 80.88, 80.185, 80.287 [703, 703.65]	1.0K	Mar 27, 2019
EuroINR 80.783, 80.783, 80.783, 81.05 [5, 4.74]	1.0K	Apr 26, 2019
GBPINR 93.838, 93.878, 93.066, 93.105 [1374, 1284.21]	1.2K	Mar 27, 2019
GBPINR 93.675, 93.675, 93.675, 93.675 [1, 1.14]	3.8K	Apr 26, 2019
USDINR 70.97, 70.97, 70.475, 70.525 [10257, 7253.46]	3.2K	Mar 08, 2019
USDINR 71.015, 71.015, 70.548, 70.593 [240, 144.34]	412K	May 15, 2019
USDINR 71.165, 71.195, 70.613, 70.675 [166023, 1176699.71]	6L	Mar 27, 2019
USDINR 71.34, 71.478, 70.715, 70.758 [10257, 3568.81]	88.9K	Apr 26, 2019
USDINR 71.58, 71.58, 71.78, 71.72 [213, 1529.96]	49.9K	May 29, 2019
USDINR 71.71, 71.71, 71.78, 71.72 [81, 58.14]	97.1K	Jun 29, 2019
USDINR 72.56, 73.59, 72.56, 73.258 [50, 36.59]	50	Dec 27, 2019
YenINR 63.755, 63.755, 63.755, 63.758 [54, 288.07]	565	Mar 27, 2019
YenINR 63.8, 63.8, 63.8, 63.908 [20, 12.76]	122	Apr 26, 2019

CURRENCY FUTURES ON NSE-SE

GBPUSD 1.315, 1.315, 1.315, 1.315 [1, 1.14]	56	Mar 27, 2019
GBPINR 93.8, 93.8, 93.1, 93.1 [640, 607.48]	54	Mar 27, 2019
USDINR 71.165, 71.165, 70.675, 70.675 [18554, 6065.41]	11.3K	Mar 27, 2019

प्रमुख विदेशी मुद्राओं की दर (रुपए में)

	कल	1 दिन पहले	1 हफ्ता पहले	1 माह पहले	1 साल पहले
INR/US \$	70.280	70.490	71.820	71.560	64.960
INR/Euro	79.450	79.860	81.240	81.500	80.420
INR/Pound	92.400	92.740	94.870	92.720	90.140

DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATIONS 13 (4) AND 15 (2) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

RUCHIKA INDUSTRIES INDIA LIMITED

(CIN: L51503MH1985PLC301881)

Registered Office: 126, Damji Shamji Estate, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083. Tel No.: + 91 22 6153 0304; E-Mail ID: roc.ruchika@gmail.com; Website: www.ruchikaind.in

Open Offer for acquisition of 5,20,000 Equity Shares of ₹5 each representing 26% of the Equity Share Capital at a price of ₹8.75 per Equity Share from the Public Shareholders of Ruchika Industries India Limited ("Ruchika"/"Target Company"), in terms of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ["SEBI (SAST) Regulations, 2011"/"Regulations"] by Mr. Rajiv Chandulal Darji (hereinafter referred to as "Acquirer")

This Detailed Public Statement ("DPS") is being issued by Mark Corporate Advisors Private Limited, the Manager to the Offer ("Manager"), for and on behalf of the Acquirer, in compliance with Regulations 13(4) and 15(2) of the Regulations pursuant to the Public Announcement ("PA") submitted to BSE Limited, Mumbai ("BSE") and the Target Company on February 27, 2019 (Wednesday) and filed with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on February 28, 2019 (Thursday) in terms of Regulation 3(1) and 4 of the Regulations.

I. ACQUIRER, SELLER, TARGET COMPANY AND OFFER:

A. Information about the Acquirer:

1) **Information about Mr. Rajiv Chandulal Darji (hereinafter referred to as "Acquirer")**

1.1. Rajiv Chandulal Darji, S/o Chandulal Darji, aged about 42 years, is presently residing at A-701, Rose Mary Building, Chikwadi, Shimpoli, Next to Witty School, Borivali (West), Mumbai-400 092, Contact No.: +91 97699 27171, E-Mail ID: simplenet45@gmail.com. He is an Under Graduate from Mumbai University. His Permanent Account Number (PAN) under Indian Income Tax Act is ACHPD 1077 F. He has over thirteen (13) years of experience in the field of Real Estate Business, project planning and execution.

1.2. He is not part of any group.

1.3. As on date, the Acquirer does not hold any Equity Share in the Target Company. However, he proposes to Acquire 9,74,216 Equity Shares representing 48.71% of the Equity Share Capital of the Target Company through Share Purchase Agreement dated February 27, 2019 (Wednesday).

1.4. He has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under section 11B of the SEBI Act or any other regulations made under the SEBI Act.

1.5. The Net Worth of the Acquirer is ₹301.47 Lakhs (Rupees Three Hundred and One Lakh and Forty Seven Thousand only) as on December 31, 2018 as certified vide certificate dated January 30, 2019 issued by Mr. Piyush Jain, Chartered Accountant (Membership No. 420319), having Office at 27, 1st Floor, Tambakuwala Building, Bhawani Shankar Road, Dadar (W), Mumbai-400 028, Contact No.: +91 72838 70105, E-Mail ID: piyushchhajer@rediffmail.com.

1.6. The entities promoted/controlled/managed by the Acquirer is as under:

Sr. No.	Name of the Entities	Designation	% of total Equity Shares held/Share of Partnership
1)	KCD Infrastructure & Construction Private Limited	Managing Director	50.00%
2)	KCD & Pramukh Infra Buildcon Private Limited	Director	1.00%
3)	Pramukh & KCD Properties Private Limited	Director	1.00%
4)	Raj Skyline & KCD Builders Private Limited	Director	7.96%
5)	KCD Heritage Private Limited	Director	99.99%
6)	KCD & Shree Swami Realcon Infra Private Limited	Director	-
7)	PKCD Infra Realty Private Limited	Director	-
8)	KCD ESLE (OPC) Private Limited	Director	100.00%
9)	Prince KCD Heritage LLP	Designated Partner	5.00%
10)	Kavya KCD Buildcon LLP	Designated Partner	5.00%
11)	KCD Buildtec LLP	Designated Partner	1.00%
12)	Kavya Town KCD Developers LLP	Designated Partner	5.00%
13)	KCD Truarc Concept LLP	Designated Partner	50.00%
14)	Sattvic Hospitality LLP	Designated Partner	25.00%
15)	Ayush Infra Ventures LLP	Designated Partner	9.00%
16)	Kavya DJ Build-con LLP	Designated Partner	5.00%

2) The Acquirer did not acquire any Equity Share of the Target Company either in the current financial year or in the period of eight financial years preceding the current financial year. However, the Acquirer is acquiring 9,74,216 Equity Shares through Share Purchase Agreement at a price of ₹6 per Equity Share.

3) Neither the Acquirer nor any of the entities with whom he is associated, are in Securities related business and registered with SEBI as a Market Intermediary.

4) None of the entities promoted or controlled by the Acquirer as mentioned in point no. 1.6 above are either participating or acting in Concert with the Open Offer.

5) As on date, the Acquirer does not have any interest in the Target Company, except for the proposed acquisition of 9,74,216 Equity Shares through Share Purchase Agreement. Further, there are no Directors representing the Acquirer on the Board of the Target Company.

6) There are no persons Acting in Concert in relation to the Offer within the meaning of 2(1) (q) (1) of the Regulations.

B. Information about the Seller:

1) Pursuant to the Share Purchase Agreement ("SPA") entered on February 27, 2019 (Wednesday), the Acquirer and the Seller had agreed to acquire 9,74,216 Equity Shares of Face Value of ₹5 (Rupee Five only) each at a price of ₹6.00 (Rupees Six only) per share representing 48.71% of the Equity Share Capital from the following Shareholder of the Target Company (hereinafter referred as "Seller"/"Selling Shareholder"):

Name, PAN & Address	Part of Promoter Group (Yes/No)	Details of Shares/Voting Rights held by the Selling Shareholders			
		Pre Transaction		Post Transaction	
		No of Shares	% vis a vis total Share Capital	No of Shares	% vis a vis total Share Capital
Mr. Saurabh Dilip Pradhan PAN: AMJPP 6295 P Address: Near R.C.F, Gate No. 2, 12, Mysore Colony, Chembur, FCI, Mumbai-400 074	Yes	9,74,216	48.71%	Nil	Not Applicable
TOTAL	-	9,74,216	48.71%	Nil	Not Applicable

2) The Acquirer has issued three(3) cheques dated February 27, 2019 aggregating to an amount of ₹58,45,296 (Rupees Fifty Eight Lakhs Forty Five Thousand Two Hundred and Ninety Six only) to the Seller towards the proposed acquisition of the above Equity Shares. The said Equity Shares are lying in the Seller's Demat Account and the Delivery Instruction Slips duly signed are in the custody of Manager to the Offer. The said Equity Shares will be transferred to the Acquirer's Demat Account upon completion of the Open Offer formalities as per the terms of Share Purchase Agreement.

3) The Seller has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act, 1992, as amended or under any other regulation made under the SEBI Act, 1992.

C. Information about the Target Company-Ruchika Industries India Limited (hereinafter referred to as "Ruchika"/"Target Company"):

1) The Target Company, was incorporated in the name of 'Ruchika Electronics Limited' on May 25, 1985 under the Companies Act, 1956 within the jurisdiction of Registrar of Companies, Delhi. Further the Name of the Company was changed to 'Ruchika Industries India Limited' vide RoC Certificate dated November 23, 2001.

2) The Registered Office of the Target Company was shifted from Delhi to the State of Maharashtra and a fresh Certificate of Registration confirming the change of Registered Office was issued by Registrar of Companies, Mumbai on November 16, 2017. The current Registered Office is situated at Office No. 126, Damji Shamji Estate, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400 083. The CIN of the Company is L51503MH1985PLC301881.

3) The Target Company is engaged in the business of trading of Electronic Goods.

4) The Authorized Share Capital of the Target Company is ₹2,50,00,000 comprising of 50,00,000 Equity shares of ₹5 each. The paid-up Equity Share Capital of the Target Company is ₹1,00,00,000 comprising of 20,00,000 Equity shares of ₹5 each fully paid-up.

5) The Equity Shares of the Target Company are listed on BSE Limited, Mumbai ("BSE") having a scrip code as 540696. The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded within the meaning of explanation provided in Regulation 2(j) of the Regulations. The ISIN of the Target Company is INE185U01027.

6) As on date, the Target Company is fully compliant with the listing requirements and there has not been any non-listing of Equity Shares on any of the Stock Exchanges.

7) The key financial information of the Target Company are based on un-audited financial statement for the period ended December 31, 2018 and audited financial statements for Financial Year ended March 31, 2018, March 31, 2017 and March 31, 2016 and the same are as follows:

(Amount in Lacs, except EPS)

Particulars	Period Ended December 2018 (Un-Audited)	FY 2017-2018 (Audited)	FY 2016-2017 (Audited)	FY 2015-2016 (Audited)
Total Revenue	7.69	62.15	138.94	21.61
Profit/(Loss) for the year/period	2.40	1.64	0.49	0.77
EPS (per share)	0.12	0.16	0.05	0.08
Net Worth/Shareholders' Fund	315.29	312.89	311.25	310.76

8) The Board of Directors of the Target Company consists of Mr. Govind Adya Chaubey, Executive Director (DIN: 08307697), Mrs. Zakhana Naineshkumar Gandhi, Non-Executive Director (DIN: 05122611), Mr. Rajni Jethalal Shah, Independent Director (DIN: 07008158) and Mr. Satishkumar Phoolchand Rajbhar, Independent Director (DIN: 06798717).

9) The Compliance Officer of the Target Company is Ms. Geeta Kalita, Company Secretary.

D. Details of the Offer:

1) The Acquirer is giving this Open Offer to acquire up to 5,20,000 Equity Shares of ₹5 each, representing 26% of the Equity Share Capital of the Target Company at a price of ₹8.75 (Rupees Eight and Paise Seventy Five only) per Equity Share ("Offer Price") aggregating to ₹45,50,000 (Rupees Forty Five Lakhs and Fifty Thousand only), payable in cash, subject to the terms and conditions set out in the Public Announcement ("PA"), this Detailed Public Statement ("DPS") and the Letter of Offer ("LoF"), which will be sent to the Public Shareholders of the Target Company.

2) All the owners of the equity shares of the Target Company registered or unregistered except the Acquirer are eligible to participate in the Offer in terms of Regulation 7(6) of the Regulations.

3) As on date, to the best of knowledge and belief of the Acquirer, there are no other statutory approvals required to acquire the equity shares tendered pursuant to this Offer. If any other statutory approvals are required or become applicable at a later date before the completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals. The Acquirer will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the Regulations.

4) This Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance by the Equity Shareholders of the Target Company in terms of Regulation 19(1) of the Regulations.

5) This is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the Regulations.

6) The Equity Shares of the Target Company which will be acquired by the Acquirer are fully paid up, free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.

7) As on date, there are no instruments pending for conversion into Equity Shares.

8) The Manager to the Offer viz., Mark Corporate Advisors Private Limited does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of appointment to act as Manager to the Offer. They declare and undertake that they shall not deal in the Equity Shares of the Target Company during the period commencing from the date of their appointment as Manager to the Offer till the expiry of 15 days from the date on which the payment of consideration to the shareholders who have accepted the Open Offer is made, or the date on which the Open Offer is withdrawn as the case may be.

E. The Acquirer does not have any plans to alienate any significant assets of the Target Company whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise for a period of two (2) years except in the ordinary course of business. The Target Company's future policy for disposal of its assets, if any, within two (2) years from the completion of Offer will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and subject to the approval of the shareholders through Special Resolution passed by way of postal ballot in terms of Regulation 25(2) of the Regulations.

F. As per Regulation 38 of SEBI (LODR) Regulations read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR"), the Target Company is required to maintain at least 25% Public Shareholding, on continuous basis for listing. Pursuant to completion of this Offer, assuming full acceptance, the Public Shareholding in the Target Company will not fall below the minimum public shareholding requirement as per SCRR as amended and the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

II. BACKGROUND TO THE OFFER:

1) As on date, the Acquirer does not hold any Equity Share in the Target Company.

2) The Offer Price is payable in cash, in accordance with Regulation 9(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.

3) At present, the Acquirer does not have any plans to make major changes to the existing line of business of the Target Company except in the ordinary course of business. The Acquirer may expand the existing business of the Target Company and may diversify into new businesses with the prior approval of the Shareholders. The Acquirer may reorganize the present Capital structure of the Company and also further strengthen the Board.

4) The Object of the acquisition is substantial acquisition of Shares/Voting Rights and take control over the Management of the Target Company.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS:

The current and proposed Equity Shareholding of the Acquirer in the Target Company and the details of their acquisitions are as follows:

Particulars	Shareholding as on PA date		Shares agreed to be acquired through SPA		Shares acquired between PA date and the DPS date		Shares proposed to be acquired in the Offer (assuming full acceptance)		Post Offer shareholding as on 10th working day after closing of Tendering Period	
	No of Shares	%	No of Shares	%	No of Shares	%	No of Shares	%	No of Shares	%
Acquirer	Nil	N.A	9,74,216	48.71	Nil	N.A.	5,20,000	26.00	14,94,216	74.71
TOTAL	Nil	N.A	9,74,216	48.71	Nil	N.A.	5,20,000	26.00	14,94,216	74.71

IV. OFFER PRICE:

1) The Equity Shares of the Target Company are presently listed on BSE Ltd, Mumbai ("BSE") having a scrip code as 540696.

2) The annualized trading turnover of the Equity Shares of the Target Company during Twelve (12) calendar months preceding the month of PA February 2018 to January 2019 on the Stock Exchange on which the Equity Shares of the Target Company are listed is given below:

Name of the Stock Exchange	Total Number of shares traded during the preceding 12 calendar months prior to the month of PA	Total No. of Equity Shares listed	Annualized trading turnover (as % of total number of listed shares)
BSE Ltd.	Nil	20,00,000	N.A

(Source: www.bseindia.com)

3) Based on the above, the Equity Shares of the Target Company are infrequently traded during twelve (12) calendar months preceding the calendar month in which PA is made within the meaning of explanation provided in Regulation 2(j) of the Regulations.

4) The Offer Price of ₹8.75 (Rupees Eight and Paise Seventy Five only) is justified in terms of Regulation 8(2) of the Regulations on the basis of the following:

Sr. No.	Particulars	Amount (In. ₹)
a)	Negotiated Price as per SPA	: 6.00
b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirer, during 52 weeks preceding the date of PA	: N.A
c)	The highest price paid or payable for any acquisition, by the Acquirer, during 26 weeks preceding the date of the PA	: N.A
d)	The volume-weighted average market price of Equity shares of the Target Company for a period of sixty (60) trading days immediately preceding the date of PA as traded on BSE, being the Stock Exchange where the maximum volume of trading in the shares of the Target Company are recorded during such period, the Equity Shares being infrequently traded	: N.A
e)	Other Financial Parameters as at:	December 31, 2018 (Unaudited)
i)	Return on Net Worth (%)	: 0.76%
ii)	Book Value Per Share	: 15.76
iii)	Earnings Per Share (₹)	: 0.12

Note: The Trading data with respect to BSE has been downloaded from website of BSE i.e. www.bseindia.com.

5) The Fair Value of the Target Company is ₹8.70 (Rupees Eight and Paise Seventy only) per share as certified vide Valuation Report dated February 27, 2019 issued by Mr. Deepak Kharwad (Membership No. 124599), Partner of M/s Jitendra Chandulal Mehta and Co., Chartered Accountants (FRN: 104288W) having office at 92-B, Visaria Sadan, 1st Floor, Belgrami Road, Near Bhabha Hospital Kurla (W), Mumbai-400 070 Tel. No.: +91 22 2650 1357.

The Offer Price of ₹8.75 (Rupees Eight and Seventy Five only) per share have been determined taking into account the methodology adopted under Hindustan Lever Employees Union v/s Hindustan Lever Ltd case.

6) In view of the parameters considered and presented in the table above and in the opinion of the Acquirer and Manager to the Offer, the Offer Price of ₹8.75 (Rupees Eight and Paise Seventy Five only) per Equity Share is justified in terms of Regulation 8 (2) of the Regulations.

7) There have been no corporate actions in the Target Company warranting adjustment of relevant price parameters.

8) As on date, there is no revision in the Offer Price or Offer Size. In case of any revision in the Offer Price or Offer Size, the Acquirer shall comply with regulation 18 of the Regulations and all the provisions of the Regulations which are required to be fulfilled for the said revision in the Offer Price or Offer Size.

9) If the Acquirer acquires or agrees to acquire any Equity Shares or Voting Rights in the Target Company during the offer period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer Price, the Offer Price shall stand revised to the highest price paid or payable for any such acquisition in terms of Regulation 8(8) of Regulations. Provided that no such acquisition shall be made after the third working day prior to the commencement of the tendering period and until the expiry of the tendering period. Further, in accordance with regulations 18(4) and 18(5) of the Regulations, in case of an upward revision to the Offer Price or to the Offer Size, if any, on account of competing offers or otherwise, the Acquirer shall (i) make public announcement in the same newspapers in which this DPS has been published; and (ii) simultaneously notify to SEBI, BSE and the Target Company at its registered office. Such revision would be done in compliance with other formalities prescribed under the Regulations.

10) If the Acquirer acquires Equity Shares of the Target Company during the period of twenty-six weeks after the tendering period at a price higher than the Offer Price, the Acquirer shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all shareholders whose shares have been accepted in the Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another Open Offer under Regulations, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of shares of the Target Company in any form.

11) If there is any revision in the offer price on account of future purchases/competing offers, or any other ground it will be done only up to the period prior to three (3) working days before the date of commencement of the Tendering Period and would be notified to the shareholders.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS:

1) The total funds required for the implementation of the Offer (assuming full acceptance), i.e., for the acquisition of 5,20,000 fully paid up Equity Shares of Face Value ₹5 each at a price of ₹8.75 (Rupees Eight and Paise Seventy Five only) per Equity Share is ₹45,50,000 (Rupees Forty Five Lakhs Fifty Thousand only) ("Maximum Consideration").

2) In accordance with Regulation 17(4) of Regulations, the Acquirer has opened a Cash Escrow Account under the name and style of 'RUCHIKA-OPEN OFFER-CASH ESCROW ACCOUNT' ("Escrow Account") with IndusInd Bank Limited ("Escrow Banker") bearing

account number 250556040665 and deposited an amount of ₹12.00 Lakhs (Rupees Twelve Lakhs only), in cash, being more than 25% of the Maximum Consideration on March 02, 2019. The Acquirer has authorized the Manager to the Offer to operate and realize the value of the Escrow Account in terms of the Regulations. The cash deposit in the Escrow Account has been confirmed vide the Certificate dated March 06, 2019 issued by the Escrow Banker.

3) The Acquirer has adequate financial resources and has made firm financial arrangements for implementation of the Open Offer, in terms of Regulation 25(1) of the Regulations. The Open Offer obligation shall be met by the Acquirer through his own resources and no borrowings from any bank and/or financial institution are envisaged. Mr. Piyush Jain, Chartered Accountant (Membership No. 420319), having Office at 27, 1st Floor, Tambakuwala Building, Bhawani Shankar Road, Dadar (W), Mumbai-400 028, Contact No.: +91 72838 70105, E-Mail ID: piyushchhajer@rediffmail.com vide Certificate dated February 27, 2019 has certified that sufficient resources are available with the Acquirer for fulfilling the obligations under this 'Offer' in full.

4) Based on the above, the Manager to the Offer is satisfied that the firm arrangements have been put in place by the Acquirer to implement the offer in full in accordance with the Regulations.

5) In case of upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size, the Acquirer shall deposit additional appropriate amount into an Escrow Account to ensure compliance with Regulation 18 (5) of the Regulations, prior to effecting such revision.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS REQUIRED FOR THE OFFER:

1) As of the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirer, there are no Statutory Approvals required by the Acquirer to complete this Offer. In case, if any Statutory Approval(s) are required or become applicable at a later date before the closure of the Tendering Period, the Offer shall be subject to the receipt of such Statutory Approval(s). The Acquirer shall make the necessary applications for such Statutory Approvals. In the event of non-receipt of any of such Statutory Approvals which may become applicable for the purchase of the Equity Shares under this Offer, the Acquirer shall have the right to withdraw the Offer in accordance with the provisions of Regulation 23(1) of the Regulations.

In the event of withdrawal of this Offer, for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, a Public Announcement will be made within two (2) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and copy of such Public Announcement will also be sent to SEBI, Stock Exchange(s) and to the Target Company at its Registered Office.

2) In case of delay in receipt of any Statutory Approval(s), pursuant to Regulations 18(11) of the Regulations, SEBI may, if satisfied, that delay in receipt of requisite Statutory Approval(s) was not attributable to any willful default, failure or neglect on the part of the Acquirer to diligently pursue such approvals, may grant an extension of time for the purpose of the completion of this Offer, subject to Acquirer agreeing to pay interest for the delayed period, provided where the Statutory Approval(s) extend to some but not all Equity Shareholders, the Acquirer has the option to make payment to such Shareholders in respect of whom no Statutory Approval(s) are required in order to complete this Open Offer. Further, in case the delay occurs on account of willful default by the Acquirer in obtaining any Statutory Approval(s) in time, the amount lying in the Escrow Account will be liable to be forfeited and dealt with pursuant to Regulation 17(10)(e) of the Regulations.

3) NRI and OCB holders of the Equity Shares, if any, must obtain all requisite approvals required to tender the Equity Shares held by them in this Offer (including, without limitation, an approval from the RBI, since the Equity Shares validly tendered in this Offer will be acquired by a non-resident entity), and submit such approvals along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement and other documents required to accept this Offer. Further, if holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs, FIs, FPIs) had required any approvals (including from the RBI or the FIPB or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit copies of such previous approvals, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. If such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares tendered pursuant to this Offer.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITIES PERTAINING TO THE OFFER:

Nature of Activity	Date	Day
Date of the PA	February 27, 2019	Wednesday
Date of publishing the Detailed Public Statement	March 07, 2019	Thursday
Last date for filing of Draft Letter of Offer with SEBI	March 14, 2019	Thursday
Last date of a competing offer	March 29, 2019	Friday
Latest date by which SEBI's observations will be received	April 05, 2019	Friday
Identified Date*	April 09, 2019	Tuesday
Last date by which the Letter of Offer will be dispatched to the Shareholders (<i>Except the Acquirer and the Selling Shareholder</i>) as on the Identified Date	April 16, 2019	Tuesday
Last date by which the recommendation of the committee of Independent Directors of the Target Company will be given and published	April 22, 2019	Monday
Last Date for revising the Offer Price/ number of shares	April 24, 2019	Wednesday
Date of Public Announcement for Opening the Offer	April 24, 2019	Wednesday
Date of Commencement of the Tendering Period ("Offer Opening date")	April 25, 2019	Thursday
Date of Closing of the Tendering Period ("Offer Closing date")	May 09, 2019	Thursday
Last date for communicating Rejection/acceptance and payment of consideration for accepted equity shares or equity share certificate/return of unaccepted share certificates/credit of unaccepted shares to demat account	May 23, 2019	Thursday

*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders (except the Acquirer and the Selling Shareholder) as on such date to whom the Letter of Offer will be sent. It is clarified that all the Public and Promoter/Promoter Group Shareholders (registered or unregistered) of the Target Company, are eligible to participate in this Offer any time during the tendering period of the Offer.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER:

1) All the Public Shareholders (*except the Acquirer and Seller*) holding the Equity Shares in dematerialized form, registered or unregistered, are entitled to participate in this Offer, any time before the closure of the tendering period of this Offer. Please note that no shares will be accepted in physical mode pursuant to PR No.: 51/2018 dated December 03, 2018 issued by SEBI wherein requests for effecting transfer of securities shall not be processed after March 31, 2019 unless the securities are held in the dematerialized form with a depository.

2) Persons who acquired Equity Shares of the Target Company but (a) who have not received the Letter of Offer ('LoF'), (b) who have acquired the Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company as on the Identified Date or unregistered owners may participate in this Open Offer.

3) The Open Offer will be implemented by the Company through Stock Exchange Mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of a separate window ("Acquisition Window") as provided under Circular Nos. CIR/CFD/POL



MEET THE NEW ICONS IN THE MAKING



WINNER
NIMESH SHAH
School of Petroleum Management,
PDPU, Gandhinagar



1st RUNNER UP
HARSHIL SHAH
K J Somaiya Institute of
Management & Research, Mumbai



2nd RUNNER UP
SHAILESH MAHAJAN
NITIE,
Mumbai



Smart solutions.
Strong relationships.

CG Power and Industrial Solutions Limited
(Formerly Crompton Greaves Limited)

Business Standard

Best B-School
Project Award 2018

THE JURY

AJIT BALAKRISHNAN
Founder & CMD,
Rediff.com

NISHI VASUDEVA
Former CMD, Hindustan
Petroleum Corporation Ltd.

AMBI PARAMESWARAN
Founder,
Brand-Building.com

RAJAT GUPTA
Senior Partner,
McKinsey

HASIT JOSHIPURA
Senior VP and Head,
Electrical & Automation, L&T

KINJAL MEDH
Head - Marketing,
National Stock Exchange

RAMESH IYER
General Manager - HR,
CG Power & Industrial Solutions Ltd.

Business Standard

Insight Out

Co-Sponsor: IndianOil

Official Tabulator: EY Building a better working world

Venue Partner: IBS[®] ICFAI BUSINESS SCHOOL

BS conferences]



‘राफेल के दस्तावेज चोरी’

सरकार ने कहा है कि वह उन अखबारों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के बारे में विचार कर रही है, जिन्होंने रक्षा सौदे के ब्योरे प्रकाशित किए हैं

आशिष आर्यन

समाचार-पत्रों ने जिन दस्तावेजों के आधार पर फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में कथित गड़बड़ियों को लेकर ब्योरे प्रकाशित किए हैं, वे रक्षा मंत्रालय से इसी मंत्रालय के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों द्वारा चुराए गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में यह बात कही।

महान्यायवादी के के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि ये दस्तावेज रक्षा सौदों से संबंधित हैं और शासकीय गोपनीयता अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसलिए सरकार उन समाचार पत्रों के खिलाफ ‘आपराधिक कार्रवाई’ के बारे में विचार कर रही है, जिन्होंने ये खबरें प्रकाशित की हैं। सरकार उन याचियों पर भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने इनका अपनी याचिका में इस्तेमाल किया है।

महान्यायवादी वेणुगोपाल ने कहा कि इन खबरों और याचिकाओं में ऐसे अति गोपनीय रक्षा दस्तावेज शामिल हैं, जिन्हें चुराया गया है।

सशस्त्र बलों ने मांगा अतिरिक्त साजो-सामान

अभिषेक रक्षित

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) से विशेष सामान की अतिरिक्त मांग की है। बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा यह पृष्ठ जाने पर कि क्या भारतीय सशस्त्र बलों की किसी इकाई ने रक्षा सामानों की तेज डिलिवरी या अतिरिक्त ऑर्डर की मांग की थी, ओएफबी अध्यक्ष सौरभ कुमार ने कहा, ‘भारतीय

सशस्त्र बलों की तीनों इकाइयों के पास रक्षा सामानों की कोई कमी नहीं है और उनको पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। हालांकि हाल के दिनों में कुछ अतिरिक्त मांग की गई है।’ वह सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

यह पृष्ठ जाने पर कि अगर थल सेना की ओर से कोई मांग आई, कुमार ने कहा, ‘इस बार, यह हवाई कार्रवाई थी।’ हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से बताने से मना कर

दिया। ओएफबी पश्चिम बंगाल में अपने एक कारखाने में एंटी-एयरक्राफ्ट गन के निर्माण को भी दोबारा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘अब भारत तथा विदेश से इन उपकरणों की मांग बढ़ रही है।’ ओएफबी आयुध तथा रक्षा उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के लिए दूसरे देशों से भी बातचीत कर रही है।

ओएफबी वर्ष 1962 से एंटी-एयरक्राफ्ट गन का उत्पादन कर रही है और उसने वर्ष 1999 में

!अदालत में सुनवाई

■केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कही दस्तावेज चोरी की बात

■महान्यायवादी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों ने चुराए दस्तावेज

■सरकार ने अदालत में राफेल मामले से जुड़ी समीक्षा याचिका खारिज करने की मांग की

हालांकि इस संबंध में अभी तक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं कराई गई है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाला तीन सदस्यीय पीठ उन याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था, जिनमें राफेल लड़ाकू विमान सौदे की खरीद में जांच को खारिज करने वाले अदालत के फैसले की समीक्षा की गुजारिश की गई थी। यह समीक्षा याचिका पूर्व केंद्रीय

मंत्री यशवंत सिन्हा एवं अरुण शौरी और वरिष्ठ अधिकृता प्रशांत भूषण ने दायर की है।

शीर्ष अदालत ने 14 दिसंबर को वे सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिनमें फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान सौदे की खरीद की अदालत की निगरानी में जांच का आग्रह किया गया था। उस समय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उसे ‘फैसले की प्रक्रिया में संदेह लायक कोई चीज नहीं मिली है’ और वह इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

उस समय न्यायालय ने कहा था, ‘इस अदालत को ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही है, जिसके आधार पर वह भारत सरकार के 36 रक्षा विमान खरीद के संवेदनशील मुद्दे में हस्तक्षेप करे। लोगों की धारणा वह आधार नहीं हो सकती, जिस पर अदालत ऐसे मामलों में जांच का आदेश दे।’ शीर्ष अदालत के समक्ष पेश समीक्षा याचिका में सिन्हा, शौरी और भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार ने लड़ाकू विमान सौदे से संबंधित अहम तथ्य छिपाए हैं और इसलिए अदालत को गुमराह किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब उच्चतम न्यायालय मूल याचिका पर सुनवाई कर रहा था, तब अदालत ने केंद्र की तरफ से सौंपे गए नोट के ‘स्पष्ट रूप से गलत’ दावों पर भरोसा किया।

भूषण ने सरकार के इस आग्रह का विरोध किया कि इस लड़ाकू विमान सौदे में जांच का आदेश देना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह होगा और इसलिए मामले में न्यायालय दखल न दे। भूषण ने कहा कि यह अचंभित करने वाली बात है। भूषण ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत में कहा, ‘यह अचंभित करने वाली बात है कि रक्षा सौदे के मामले में अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो जांच एजेंसी का यह कर्त्तव्य है कि वह इस अदालत की संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक जांच करे। यह अलग चीज है कि अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वे क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करें।’ भूषण ने सीएजी की रिपोर्ट पर भी अचंभा जताया, जिसमें राफेल लड़ाकू विमान की कीमत से संबंधित ब्योरों को संपादित किया गया है। यह रिपोर्ट हाल में संसद में पेश की गई थी। भूषण ने कहा, ‘सीएजी के रक्षा सौदे की ऑडिट में कीमत से संबंधित सभी जानकारीयं दी जाती हैं। सीएजी के इतिहास में पहली बार सरकार के कहने पर कीमत ब्योरों को संपादित किया गया है।’ इस मामले की अदालत में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।

कमी के चलते उत्पादन काफी मंद पड़ गया।

कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना ने 114 लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन (धनुष) का ऑर्डर दिया है जिसे ओएफबी द्वारा विकसित किया जाता है। कुमार को उम्मीद है कि भारतीय सेना से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद 155 एमएम मॉर्डन आर्टिलरी गन-धनुष की मांग बढ़ेगी। इसके उत्पादन में 81 प्रतिशत स्वदेशी सामान का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में ओएफबी के पास करीब 1,000 करोड़ रुपये कीमत की धनुष आर्टिलरी गन के ऑर्डर हैं।



अपनी क्षमता को बढ़ाकर 12.7 एमएम एयर डिफेंस गन का भी उत्पादन करने लगी थी। हालांकि इस तरह के उपकरणों की मांग में

‘सैटेलाइट तस्वीरों में नहीं दिखता नुकसान’

जैश के बालाकोट ठिकाने के भारतीय हवाई हमले में तबाह हो जाने के दावे पर सैटेलाइट तस्वीरों से खड़े हुए सवाल

रॉयटर्स

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में यह पाया है कि पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का प्रशिक्षण शिविर अब भी उसी तरह दिख रहा है जैसा वह भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के पहले था।

रॉयटर्स ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित निजी सैटेलाइट संचालक फर्म प्लेनेट लैब्स इंक से मिली तस्वीरों का विशेषज्ञों के जरिये विश्लेषण कराने के बाद यह सनसनीखेज दावा किया है। रॉयटर्स ने इस विश्लेषण में पाया है कि जैश के नियंत्रण वाले इस परिसर में हवाई हमले के छह दिन बाद 4 मार्च को भी 6 इमारतें मौजूद हैं।

हालांकि एक अन्य समाचार एजेंसी के अनुसार सरकारी सूत्रों ने नई दिल्ली में बताया कि भारतीय वायु सेना ने सरकार को रडार और उपग्रह तस्वीरें सौंपी हैं। इन तस्वीरों में पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर के ‘लक्षित निशाने’ पर बमबारी और उसे भारी नुकसान दिख रहा है।

यह दावा भारतीय वायुसेना के हमले में जैश का यह ठिकाना ध्वस्त होने पर सवाल खड़े करता है। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को तड़के बालाकोट के पहाड़ी इलाके में मौजूद इस शिविर पर बम बरसाए थे। इस हमले में आतंकवादियों के बड़ी संख्या में



मारे जाने की बात कही गई थी। अर्द्धसैनिक बल सीआरपीएफ के काफिले पर पुलवामा में हुए आत्मघाती धमाके की जिम्मेदारी जैश ने ली थी। उसके बाद ही बालाकोट में मौजूद जैश के इस प्रशिक्षण शिविर को वायुसेना ने निशाना बनाया था (उस हमले में

आतंकियों को प्रशिक्षण देने वाले इस शिविर को हुए नुकसान और मारे गए आतंकवादियों की संख्या को लेकर असमंजस बना हुआ है। जहां सरकार ने मारे गए लोगों की सटीक संख्या को लेकर कोई दावा नहीं किया है वहीं इस पर राजनीतिक दलों में खींचतान मची हुई है। हालांकि अभी तक उस शिविर के बारे में उच्च गुणवत्ता वाली सैटेलाइट तस्वीर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होने से इन दावों की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। लेकिन प्लेनेट लैब्स से मिली तस्वीरें 72 सेंटीमीटर तक की बारीक जानकारी को भी कैद किए हुए हैं। इतने करीब से खिंची गई तस्वीरों से पता चलता है कि 4 मार्च को उस जगह पर अब भी 6

रॉयटर्स के मुताबिक हमले के छह दिन बाद भी जैश के ठिकाने की 6 इमारतें मौजूद थीं

इमारतें मौजूद हैं।अगर इस परिसर की अप्रैल 2018 को ली गई एक अन्य तस्वीर से तुलना करें तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं दिखता है। इमारतों पर बम गिरने से होने वाले नुकसान की कोई भी निशानी नहीं नजर आ रही है। न तो दीवारों पर जलने के निशान हैं और न ही हमले से बने गड्ढे नजर आते हैं। यहां तक कि आसपास के पेड़ भी सही-सलामत नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में महारत रखने वाले जेफ्री लेक्सि ने 4 मार्च को ली गई तस्वीरों में 6 इमारतें मौजूद होने की पुष्टि की है। मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पूर्व-एशिया अप्रसार परियोजना के निदेशक जेफ्री ने कहा, ‘उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों में बम से हुए नुकसान का कोई साक्ष्य नहीं दिख रहा है।’ उन्होंने कुछ घंटों के ही भीतर ली गई तीन अन्य तस्वीरों

को भी देखने के बाद यह निष्कर्ष रखा है। अगर प्लेनेट लैब्स की इन तस्वीरों पर यकीन करते हैं तो

हवाई हमले में शिविर को तबाह कर देने का दावा संदेह के घेरे में आ जाता है।

सुरक्षा भी, समृद्धि भी

SHRIRAM UNNATI
FIXED DEPOSITS

9.25%*

तक वार्षिक ब्याज

क्रिसिल FD रेटिंग

"FAAA/Stable"

वरिष्ठ नागरिकों के लिए

अतिरिक्त वार्षिक ब्याज 0.25%

टोल फ्री नं.: 1800 103 4959

वेबसाइट: www.stfc.in

5 वर्ष के डिपॉजिट पर

कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर (सीआईएन): L65191NT1979PLCOO7874.

SHRIRAM

Transport Finance Company Limited

A WINNING RELATIONSHIP

APPOINTMENTS

विजया बैंक

VIJAYA BANK

A friend you can bank upon

मुख्यालय: 41/2, एम.जी. रोड, ट्रिनिटी सॉकिल, बेंगलूरु-560 001

मर्ती अधिसूचना सं. 01/2019 एवं 02/2019

विजया बैंक, एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, जिसका अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व के साथ मुख्यालय बेंगलूरु में है, पूरे भारत में बैंक की विभिन्न शाखाओं के लिए “बपरासी (310 रिक्तियां), स्वीपर (126 रिक्तियां)” के पद के लिए आवेदन (केवल ऑनलाइन) आमंत्रित करता है। राज्य-वार रिक्तियां एवं विस्तृत विज्ञापन बैंक की वेबसाइट www.vijayabank.com पर प्रदर्शित किया गया है।

बेंगलूरु

दिनांक: 07.03.2019

निर्मला श्रीधर

महाप्रबंधक-कार्गिक

धमकियों और गालियों से नहीं परेशान : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और कर्नाटक में जनसभाएं संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना

- मोदी ने कहा, विपक्ष देश को आगे ले जाने की योजना स्पष्ट रूप से बताए
- राहुल ने कहा, राफेल दस्तावेजों की चोरी मामले पर पर्दा डालने की कोशिश
- विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर कसा तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह खुद को मिल रही धमकियों और गालियों से परेशान नहीं हैं और वह भारत को मजबूत बनाने के लिए हर जरूरी काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी हत्या किए जाने संबंधी कांग्रेस नेता की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा, ‘मैं धमकियों और गालियों को लेकर परेशान नहीं हूं। भारत को मजबूत करने के लिए जो कुछ जरूरी है, उसे करूंगा।’ मोदी ने विपक्ष की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि वे लोग राजनीति और स्वार्थी हितों से दिशानिर्देशित हैं और कभी मजबूत भारत या मजबूत सशस्त्र बल नहीं चाहा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को राष्ट्र को आगे ले जाने की अपनी योजना को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। उन्होंने विपक्ष के खिलाफ अपने महामिलावट तंज को भी दोहराया। मोदी ने यह याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए लगभग 50 (राज्य) सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। उन्होंने एम. के. स्टालिन नीत पार्टी (द्रमुक) पर प्रहार करते हुए कहा, ‘मूल्यों से ऊपर अवसरवादिता हो गई है।’ अन्नाद्रमुक के साथ

भाजपा का चुनावी गठबंधन होने के बाद मोदी ने तमिलनाडु में अपनी प्रथम जनसभा में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर राज्य के दिवंगत मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन के नाम पर करने की घोषणा की। मोदी ने कहा कि राज्य के सत्तारूढ़ दल की काफी समय से लंबित एक मांग पूरी करते हुए हमने चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम महान एमजीआर के नाम पर करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को कर्नाटक के लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में एक पूर्ण बहुमत की सरकार चुनने का आग्रह करते हुए इस बात पर बल दिया कि महामिलावट सरकार आधा परिणाम देगी। मोदी ने साथ ही भाजपा विरोधी गठबंधन बनाने के विपक्षी दलों के प्रयासों को स्वार्थ की राजनीति बताते हुए निशाने पर लिया और कहा कि वे केवल मोदी हटाओ एजेंडे से निर्देशित हैं। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ में आयोजित एक जनसभा में मोदी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने पर वायुसेना के हवाई हमले की ओर इशारा करते हुए आज अपने दमखम की बात की। उन्होंने कहा, ‘वह मोदी के कारण नहीं बल्कि 125 करोड़ लोगों के (संकल्प) चलते हुआ।’ उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में एक निरीह सरकार है। मोदी ने कहा कि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और जदएस अलग-अलग दिशा में खींच रहे हैं।

प्रधानमंत्री पर मुकदमे के लिए पर्याप्त सबूत: राहुल

राफेल विमान सौदे से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि इस घोटाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि दस्तवेजों के चोरी होने की बात करना सबूत को नष्ट करना और मामले पर पर्दा डालने की कोशिश है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘राफेल घोटाले में प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए अब पर्याप्त सबूत है। भ्रष्टाचार की शुरुआत उन्हीं से होती है और उन पर ही खत्म होती है।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ‘राफेल मामले की अहम फाइलों से वह फंस रहे थे।’ अब सरकार ने कहा कि ये फाइलें चोरी हो गई हैं। यह सबूत को नष्ट करना और मामले पर पर्दा डालना है।

कितने मच्छर मारे, ये गिनने बैठूं या सो जाऊं ? : सिंह

पाकिस्तान में वायुसेना की कार्रवाई में मारे गए आतंकवादियों की संख्या के संदर्भ में कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप बुधवार को भी जारी रही। कांग्रेस नेताओं के बयान पर तंज कसते हुए विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने पूछा कि रात में हिट से कितने मच्छर मारे, उसे गिनने बैठूं या आराम से सो जाऊं ? *भाषा*

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

Bank of Baroda

भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

7%

7.65%

आकर्षक ब्याज दरों का लाभ उठाएं.

बड़ौदा समृद्धि जमा योजना

444 दिनों की सावधि जमा के साथ

हमें फॉलो करें

[f](#)
[t](#)
[i](#)
[g](#)
[y](#)

पात्रता

प्रि मैच्योर आहरण के विकल्प सहित लागू ब्याज दर

बगैर प्रि मैच्योर आहरण विकल्प पर लागू ब्याज दर (न्यूनतम जमा राशि ₹15.01 लाख)

सामान्य नागरिक

7.00%

7.15%

वरिष्ठ नागरिक

7.50%

7.65%

टोल फ्री नंबर पर कॉल करें: 1800 258 44 55, 1800 102 44 55

www.bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा